

सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच



वर्ष- 18 अंक - 45 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शनिवार 28 नवम्बर 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास - खबर

दिल्ली में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ रहे तार, एजेंसियां कई दिन से रख रही थीं नजर

दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक, संदिग्ध की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। पूछताछ के बाद उसे कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि उसका गुजरात में पकड़े गए जैश के संदिग्ध आतंकी से कोई संबंध है या नहीं। दिल्ली पुलिस अब आतंकी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। शुरुआती जानकारी से ऐसे संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं को भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। गिरफ्तार संदिग्ध को भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही भर्ती किया गया था। अब जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या उसका गुजरात एटीएस द्वारा 27 नवंबर को वडोदरा में गिरफ्तार किए गए जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध से कोई संबंध है। गुजरात एटीएस ने संदिग्ध को एक एके-47 राइफल और 23 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था।

गड्ढे में फंसे नन्हे हाथी को वन विभाग ने सुरक्षित निकाला

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर इलाके में हाथियों का एक दल विचरण कर रहा था। इसी दौरान झुंड का एक नन्हा शावक गड्ढे में गिरकर फंस गया। शावक को मुसीबत में देख हाथियों का पूरा झुंड उसके आसपास जमा हो गया और सुरक्षा घेरा बना लिया। ऐसी स्थिति में शावक तक पहुंचना वन विभाग की टीम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरनाक था। हाथियों के झुंड की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग की टीम ने पहले झुंड को सुरक्षित दूरी पर खदेड़ा, जिसके बाद शावक को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम ने लगातार करीब तीन घंटे तक कड़ी मशक्कत की। आखिरकार टीम को सफलता मिली और नन्हे शावक को सुरक्षित गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया।

डीएमके के 22 सांसद परिसीमन बिल का करेंगे समर्थन

नईदिल्ली। लोकसभा में सरकार को परिसीमन बिल पास कराने की राह आसान होती जा रही है। शरद पवार की ह्रष्टक्कऔर आंध्र प्रदेश के पूर्व ष्टरू जगनमोहन रेड्डी की ङ्कस्त्रष्टक्कके बाद शनिवार को एमके स्टालिन की पार्टी ष्ठरूच्य ने समर्थन का ऐलान किया।पार्टी की बैठक के बाद सांसद ए. राजा ने कहा कि तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 से बढ़ाकर 59 की जाएं। डीएमके चाहती है कि सीटें बढ़ने के बाद भी संसद में राज्य की हिस्सेदारी करीब 7.2 प्रतिशत बनी रहे। लोकसभा में डीएमके के 22, एनसीपी(एसपी) के 8 और वाईएसआरसीपी के 4 सांसद हैं। इस तरह इन तीनों दलों के 34 सांसदों का समर्थन मिलने से लोकसभा में ह्रष्ठ की संख्या 320 से बढ़कर 354 हो जाएगी। बिल पास कराने के लिए कुल 540 सांसदों में दो तिहाई बहुमत यानी 360 सांसदों के वोटों की जरूरत है। यानी सरकार को अभी 6 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी।

एडवोकेट जनरल ऑफिस के नाम से फर्जी वेबसाइट : ऑनलाइन जुआ और लॉटरी से जुड़े विज्ञापनों की भरमार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल कार्यालय के नाम से मिलती-जुलती पहचान वाली एक वेबसाइट पर, ऑनलाइन लॉटरी और सट्टे के विज्ञापन प्रदर्शित होने का मामला सामने आया है। वेबसाइट का नाम advocategeneralcg.com है। इसके मुख्य पेज पर ऑनलाइन जुआ और लॉटरी से जुड़े विज्ञापनों की भरमार दिखाई दे रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा ने इसे फर्जी वेबसाइट बताया है और इसके खिलाफएफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। वेबसाइट खोलने पर JARIyD नाम से ऑनलाइन सट्टे और लॉटरी का प्रचार दिखाई देता है। इसमें 'Togel Macau' और 'Toto Macau' जैसी श्रेणियां प्रदर्शित की गई हैं।



साइबर सेल और एजेंसियों से होगी जांच

मामले में एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा ने साफकिया है कि यह फर्जी वेबसाइट है और इस तरह की कोई साइट हाईकोर्ट एडवोकेट जनरल ऑफिस द्वारा नहीं बनाई गई है। उन्होंने इसके खिलाफएफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। ऐसे में अब जांच के जरिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि वेबसाइट किसने बनाई। इसका संचालन कहां से किया जा रहा है और एडवोकेट जनरल कार्यालय के नाम से मिलती-जुलती पहचान वाले डोमेन का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया।

सीजीपीएससी अध्यक्ष नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, सीएम साय बोले- जल्द होगी नियुक्ति

हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर तक मांगी प्रगति रिपोर्ट, कहा- नियुक्ति नहीं होने पर होगी सख्त कार्रवाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) में अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है किसी सीजी पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द की जाएगी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट भी में इसकी जानकारी देते हुए दो सप्ताह के भीतर करने की बात कही है।

मुख्यमंत्री श्रविष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वार्षिक परीक्षा कैलेंडर और अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि सीजीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति



जल्द की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। शासकीय सेवाओं में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को गति देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जल्द ही नए पदों के लिए वेकेंसी निकलेगी। युवाओं के भविष्य और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने दिया सुझाव

हाईकोर्ट में मनोचिकित्सक विशेषज्ञों के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू कराने में हो रही देरी का मुद्दा भी उठा। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यदि नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति में समय लग रहा है तो इंटरव्यू कराने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी हो रही देरी

हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में निर्देश देते हुए आयोग और राज्य सरकार को 10 दिन का समय दिया था। कहा था कि अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कदम उठाए जाएं। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

14 दिसंबर को फिर सुनवाई

हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी और राज्य सरकार को 14 दिसंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में नियुक्ति की प्रगति बताने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपेक्षा जताई है कि तब तक आयोग में अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होने पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

रायपुर व भाटापारा स्टेशन पर रेलवे की जांच, 3 लाख का वसूला जुर्माना

श्रीकंचनपथ न्यूज



रायपुर। रेलवे में बिना टिकट और अनियमित तरीके से यात्रा करने वालों के खिलाफ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल ने सख्ती दिखाई है। भाटापारा रेलवे स्टेशन पर किलाबंदी टिकट चेकिंग और रायपुर स्टेशन पर नाका चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 16 ट्रेनों और दोनों स्टेशनों पर सघन जांच कर कुल 325 मामले पकड़े गए। रेलवे ने इन मामलों में कुल 2 लाख 92 हजार 40 रुपये का राजस्व प्राप्त किया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. सुस्कर विपुल विलासराव के निर्देश पर चलाए गए अभियान के दौरान भाटापारा और रायपुर स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म सहित 16 ट्रेनों में सघन टिकट जांच की गई। टिकट नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। जांच अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रा करते हुए 207 यात्री पकड़े गए। इन यात्रियों से रेलवे ने 2 लाख 14 हजार 635 रुपये का जुर्माना वसूला। वहीं, अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वाले 102 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनसे 74 हजार 800 रुपये वसूले गए। इसके अलावा निर्धारित सीमा से अधिक लगेज लेकर यात्रा करने वाले 15 यात्रियों से 2 हजार 170 रुपये तथा अन्य एक मामले में 435 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस तरह अभियान के दौरान कुल 325 मामलों में कार्रवाई करते हुए रेलवे को 2 लाख 92 हजार 40 रुपये की आय हुई। इस अभियान में सहायक वाणिज्य प्रबंधक-1 (कोचिंग) राजेश कुमार साह, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक टिकट चेकिंग और 20 टिकट चेकिंग कर्मचारी शामिल रहे। टीम ने स्टेशनों और ट्रेनों में जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर कार्रवाई की।

शराब घोटाले के आरोपी के लिए देर-रात खुली कोर्ट

श्रीकंचनपथ न्यूज



रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में 1280 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में फरार आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को से भारत लाया गया है। शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे उसे रायपुर की रिमांड कोर्ट में पेश किया गया। ACB कोर्ट में जज की अनुपस्थिति के चलते उसे रिमांड कोर्ट में पेश किया गया। शराब सिंडिकेट में विकास को फंड मैनेजर यानी मनीमैन की भूमिका में बताया गया है।

इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस पर UAE की एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद EOW ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समन्वय से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी कर उसे भारत पहुंचाया। विकास UAE में रहकर बोस्टन नाम की कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। ACB-EOW ने पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विकास को 30 नवंबर तक EOW की रिमांड पर सौंप दिया। फिर रात 12:33 बजे EOW के अधिकारी उसे कोर्ट से लेकर ACB-EOW कार्यालय पहुंचे। सोमवार को उसे फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

सड़क हादसे में सांसद लक्ष्मी वर्मा चोटिल, गनमैन भी घायल

- **एम्स में भर्ती, बलौदाबाजार से लौटते वक्त खरोरा के पास कार दुर्घटनाग्रस्त**

श्रीकंचनपथ न्यूज



रायपुर। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा शुक्रवार को रायपुर और खरोरा के बीच भीषण सड़क हादसे में घायल हो गईं। इस हादसे में कार में सवार उनका बेटा, गनमैन और चालक भी गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को बेहतर उपचार के लिए एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है।

प्रा्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा सांसद के हाथ में फ्रेक्चर हुआ है। इसके अलावा उनके वाहन चालक के सीने और हाथ में गंभीर चोट आई है। दुर्घटना होते ही घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग सहायता के लिए दौड़ पड़े।

कार्यक्रम से लौटते समय हुआ हादसा

राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा बलौदाबाजार में एक कार्यक्रम में भाग लेकर कार से वापस रायपुर लौट रही थीं। इसी दौरान खरोरा के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के समय कार के अंदर सांसद के अलावा उनका बेटा, गनमैन और चालक समेत कुल चार लोग मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलते ही खरोरा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है और घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी जुटा रही है।

छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ी,18 जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से कम

श्रीकंचनपथ न्यूज



रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम साफहोने के बाद रात की ठंड बढ़ रही है। उत्तर छत्तीसगढ़ में इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। बलरामपुर-रामानुजगंज में न्यूनतम तापमान गिरकर 8.3 डिग्री पहुंच गया है।

वहीं अंबिकापुर में 8.9 और सूरजपुर में 11.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके उलट दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर और सुकमा में रातें गर्म हैं। सुकमा में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री रहा। बलरामपुर और सुकमा के तापमान में 9.9 डिग्री का अंतर है। रायपुर में भी रात का तापमान 16.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक है। हालांकि प्रदेश के मैदानी और उत्तरी जिलों में रात का पारा लगातार नीचे बना हुआ है।

धमतरी में 13, गरियाबंद में 12.3 रायगढ़ में 12.6 और कोरबा में 12.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 18 जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। राजधानी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री कम दर्ज किया गया।

गुरुग्राम से 27 बांग्लादेशी नागरिक डिपोर्ट मानेसर डिटेंशन सेंटर में पूरी हुई प्रक्रिया, पुलिस सुरक्षा में ट्रेन से रवाना



नईदिल्ली। गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे 27 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने सभी को भारी सुरक्षा और निगरानी के बीच ट्रेन से रवाना किया। सुरक्षा व्यवस्था और आम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे के समन्वय से ट्रेन में एक अतिरिक्त जनरल कोच भी अटैच करवाया गया।

पुलिस के सशस्त्र जवानों और अधिकारियों की निगरानी में सभी 27 नागरिकों को विशेष कोच में बैठाया गया। यात्रा के दौरान उनके खाने-पीने और सुरक्षा की व्यवस्था भी पुलिस टीम की देखरेख में की गई। इन बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और PO स्टाफ की अलग-अलग टीमों ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा था।

पुलिस को जिले के विभिन्न इलाकों में विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से रहने की सूचनाएं मिल रही थीं। इसके बाद टीमों ने संदिग्ध क्षेत्रों में दबिश देकर इन्हें हिरासत में लिया। जांच के दौरान भारत में प्रवेश और यहां रहने से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन इनके पास वैध पासपोर्ट, वीजा या अन्य सरकारी अनुमति नहीं मिली।

बिसलेरी पर एफएसएसएआई का एक्शनः पानी के सैंपल में मिले बैक्टीरिया, कंपनी के खिलाफ मुकदमे को मंजूरी



नईदिल्ली। बोतलबंद पानी बेचने वाली बड़ी कंपनी बिसलेरी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कंपनी पर कार्रवाई की मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल के एक प्लांट से लिए गए पानी में बैक्टीरिया मिला है। जांच के दौरान दो अलग-अलग प्रयोगशालाओं ने इसकी पुष्टि की है। इसके बाद कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है।

यह मामला पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से जुड़ा हुआ है। यहां तेलीपाड़ा गांव में बिसलेरी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संचालित होती है। इसी प्लांट से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पानी का सैंपल लिया था। जांच में इस सैंपल के अंदर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया। प्राथमिक लैब और रेफरल लैब ने भी इसकी मौजूदगी की पुष्टि की।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जांच में सामने आया कि पानी का सैंपल बैच नंबर क्क्क 201 से संबंधित था। इस रिपोर्ट के बाद स्नस्त्रद्ध ने 12 अगस्त 2026 को संबंधित बैच की बिक्री रोक दी थी। यह रोक पूरे ब्रांड के बजाय संबंधित बैच पर लगाई गई थी। अब खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि संबंधित मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। हालांकि, अभियोजन की मंजूरी का मतलब कंपनी को दोषी ठहराना नहीं है। अंतिम फैसला अदालत में पेश सबूतों और कानूनी सुनवाई के बाद होगा।



संपादकीय

सेहत का रेड अलर्ट

खाद्य पदार्थों पर चीनी-नमक-वसा की चेतावनी

भारत तेजी से मधुमेह, मोटापे और उच्च रक्तचाप के मरीजों की राजधानी बन रहा है। घर के स्वास्थ्यवर्धक खाने को तिलांजलि देकर चटपटा खाने का जुनून युवा पीढ़ी ही नहीं, पुरानी पीढ़ियों में भी नजर आ रहा है। दरअसल, चीनी व यूरोपीय शैली के खाद्य पदार्थों में तीखे नमक, चीनी तथा अधिक वसा के इस्तेमाल से चटपटे व्यंजन बनाने का जुनून आज भारतीयों के सिर चढ़कर बोल रहा है। खासकर बच्चे व नयी पीढ़ी के युवा इसके दीवाने हैं। लोक कल्याण का दम भरने वाली सरकारों की जन-स्वास्थ्य के प्रति अनदेखी के चलते जीवन शैली के तमाम रोग पनप रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाने के निर्देश देने पड़े हैं। निस्संदेह, देश मे बढ़ते जन-स्वास्थ्य संकट के बीच कोर्ट की यह सार्थक पहल है। अदालत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई को निर्देश दिया है कि जिन भी उत्पादों में चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक हो, उन पर अलग से लाल रंग की चेतावनी लगायी जाए। ऐसा करके कोर्ट ने कंपनियों की सुविधा के बजाय उपभोक्ताओं के 'जानने के अधिकार' को प्राथमिकता दी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि नियामक संस्था खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अपने दायित्वों के निर्वहन में नाकाम रही है। यही वजह है कि देश की शीर्ष अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। जन स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक मात्रा में चीनी, नमक व वसा का मुद्दा सार्वजनिक विमर्श में होने के बावजूद एफएसएसएआई कई अलग-अलग प्रस्तावों के बीच उलझा रहा। इसमें स्टार 'रेटिंग सिस्टम' भी शामिल रहा है। जिसको लेकर विषय विशेषज्ञों की राय थी कि 'स्टार रेटिंग सिस्टम' से उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य जोखिम के प्रति सचेत करने के बजाय, उनमें चयन को लेकर भ्रम बढ़ सकता है। सही मायने में ऐसे किसी निर्देश में स्पष्टता होनी बेहद जरूरी है।

> निस्संदेह, देश मे बढ़ते जन-स्वास्थ्य संकट के बीच कोर्ट की यह सार्थक पहल है। अदालत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई को निर्देश दिया है कि जिन भी उत्पादों में चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक हो, उन पर अलग से लाल रंग की चेतावनी लगायी जाए। ऐसा करके कोर्ट ने कंपनियों की सुविधा के बजाय उपभोक्ताओं के 'जानने के अधिकार' को प्राथमिकता दी है। लेकिन एक बात तो साफहै कि नियामक संस्था खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अपने दायित्वों के निर्वहन में नाकाम रही है।

विडंबना है कि देश में अत्यधिक प्रोसेस्ड यानी अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खपत में भारी वृद्धि हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि देश आज तमाम गैर-संचारी रोगों की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। फलत: भारत में मधुमेह, हाइपरटेंशन और मोटापे से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। ये रोग जीवनशैली की विसंगतियों से पैदा हुए हैं। विडंबना है कि सीधे खाने के लिये तैयार खाद्य पदार्थों, मीठे पेय पदार्थों और डिब्बाबंद स्नैक्स के लिये बेहद आक्रामक मार्केटिंग के जरिये बच्चों व युवाओं को लुभाया गया। फलत: जन-स्वास्थ्य के लिये एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में लाल चेतावनी चिन्ह लगाने का निर्देश समय की सख्त जरूरत है। इससे कंपनियां छोटे अक्षरों की आड़ में पोषण संबंधी जोखिमों को छिपा नहीं सकतीं। लाल चेतावनी पर उपभोक्ताओं का सीधा ध्यान जाएगा। रोजमर्रा के खान-पान की चीजों को चुनते समय, लोगों को जटिल पोषण तालिकाओं को समझने के लिये किसी विशेष ज्ञान या अतिरिक्त समय की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वहीं जन-स्वास्थ्य की कीमत पर उद्योग जगत को मुनाफे की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एफएसएसएआई को चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट के लिये वैज्ञानिक आधार पर तार्किक सीमाएं तय करनी चाहिए। उसे उद्योग जगत की तरफ से आने वाले किसी भी दबाव का सामना करना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके अलावा निर्माताओं को छूट का फायदा उठाने, चेतावनियों को कमजोर करने या हानिकारक तत्वों की जगह वैकल्पिक संदिग्ध पदार्थों के इस्तेमाल की किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। खासकर बच्चों को लुभाने के लिये दिए जाने वाले विज्ञापनों में किए जाने वाले दावों की बारीकी से जांच होनी चाहिए। वास्तव में चेतावनी वाले लेबल उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने के साथ ही खाद्य पदार्थों के चयन करने में मददगार हो सकते हैं। देश में हर व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसके खाद्य पदार्थ में क्या-क्या मिलाया गया है। ये व्यक्ति के स्वास्थ्य अधिकार का ही हिस्सा है। जरूरी है कि पैकेट पर मौजूद लाल चेतावनी, कंपनियों की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों के लिए एक लक्ष्मण रेखा का काम करे।

नेपाल से जुड़े विवादित मुद्दों को टाल पाया भारत

पुष्परजंन



प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण एशियाई कूटनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत-नेपाल के बीच विवादास्पद मुद्दों को दरकिनार करने पर अपने समकक्ष को राजी कराया। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत इतनी लंबी चली कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के लिए निर्धारित समय निकल गया। अंतत: उस वार्ता को रद्द कर दिया गया।

बालेन्द्र शाह की दिल्ली यात्रा कितनी सफल रही, इसका वास्तविक परीक्षण मार्च, 2027 में होने वाले स्थानीय चुनावों में होगा। वर्ष 2022 में स्थापित आरएसपी अपेक्षाकृत नई पार्टी है। 9 मार्च, 2026 को स्वत:स्फूर्त रूप से हुए आम चुनाव में बालेन्द्र-लामिछाने की पार्टी की जीत को महज भावनात्मक उबाल मानिए। लोग अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की कारगुजारियों से पक चुके थे। रैपर से राजनेता बने बालेन्द्र शाह को नेपाली जनमानस ने जमीन से जुड़ा जुझारू नेतृत्वकर्ता माना था। लेकिन अब जब आम नेपाली उन्हें गोल्फ खेलते देखता है तो ठगा-सा महसूस करता है।

नेपाल में गोल्फ राजाओं का खेल रहा है। इसकी शुरुआत और विकास राणा शासकों तथा शाही परिवार के संरक्षण में हुआ था, जिसके कारण लंबे समय तक इसे राजाओं और कुलीनों का खेल माना जाता रहा। कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी गोल्फ खेलने लगे थे। ओली को अक्तूबर, 2026 में दशहरे की छुट्टियों के दौरान काठमांडू के गोकर्ण फॉरेस्ट रिसॉर्ट में गोल्फ खेलते हुए देखा गया था। पांच महीने बाद ओली जनता के हाथों नप गए।

6 नवंबर, 2026 को रोजा लक्ज़मबर्ग फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बालेन्द्र सरकार के कामकाज को लेकर युवाओं के बीच कुछ हद तक निराशा और थकान देखी जा रही है। ये युवा अब बालेन्द्र की कार्यशैली को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। गत 10 अक्तूबर, 2026 को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, नेपाली कांग्रेस जैसी पारंपरिक पार्टियां अपने खोए हुए मतदाताओं को वापस लाने के लिए संगठनात्मक बदलाव और महाधिवेशन कर रही हैं। मधेशी नेता और वामपंथी भी आपसी मतभेद भुलाकर घर वापसी के वास्ते मशक्कत कर रहे हैं।

दिल्ली में क्या हुआ, इसकी जिज्ञासा नेपाल में उन लोगों को ज्यादा है, जो नेपाल फर्स्ट वाले राष्ट्रवादी मूड में हैं। सोमवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के बीच प्रस्तावित बैठक 30 मिनट तक चलने वाली थी। लेकिन यह बैठक काफी लंबी चली और करीब डेढ़ घंटे तक जारी रही। उस दौरान बाकी अधिकारियों को दूर रखा गया। जाहिर है, राजनयिक यही बताते हैं कि दोनों शासन प्रमुखों ने नेपाल-भारत संबंधों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मत भूलिए, नरेंद्र मोदी और बालेन्द्र शाह एक ही वंचित समुदाय से आते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच निजी संबंध प्रगाढ़ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण एशियाई कूटनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत-नेपाल के बीच विवादास्पद मुद्दों को दरकिनार करने पर अपने समकक्ष को राजी कराया। यही दिल्ली बैठक की सबसे बड़ी सफलता है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत इतनी लंबी चली कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के लिए निर्धारित समय निकल गया। अंतत: उस वार्ता को रद्द कर दिया गया।

नेपाल में 'लियो-लियो, पायो-पायो' (ले लिया-पा लिया) के नारे मुख्य रूप से रथ यात्राओं, पारंपरिक उत्सवों और सामुदायिक खेलों के दौरान उत्साह तथा सामूहिक शक्ति बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। राजनीति में भी कुछ इसी भाव से सत्ता समर्थक अति उत्साह में 'लियो-लियो, पायो-पायो' करने लगे हैं। लेकिन अभी बहुत से जटिल मुद्दों को सुलझाना बाकी है। काठमांडू-भैरहवा-लखनऊ के बीच जिस दोतरफा हवाई मार्ग पर सहमति बनी है, उस पर भी अभी तकनीकी चर्चा होनी है, खासकर भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ानों की ऊंचाई को लेकर।

दोनों देश नागरिक उड्डयन के लिए हवाई क्षेत्रों के इस्तेमाल के दौरान सैन्य ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते किन-किन उपायों पर काम करेंगे? अभी सब कुछ अंधेरे में है। जब तक इस संबंध में आधिकारिक बयान नहीं आ जाता, फेसबुकिया तुक्केबाजी जोखिम भरा काम है। गोरखपुर और बागडोगरा दोनों ही रणनीतिक रूप से अहम रक्षा केंद्र हैं, जहां मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के स्टेशन और आसपास भारतीय सेना की सैन्य इकाइयां तथा सुविधाएं मौजूद हैं।

ध्यान रहे कि भैरहवा हवाई अड्डे का निर्माण चीन की एक सरकारी कंपनी (नॉर्थवेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप) द्वारा किया गया है। इस हवाई अड्डे का रखरखाव अब भी चीन के जिम्मे है। यह हवाई अड्डा भारत-नेपाल सीमा (उत्तर प्रदेश के सोनौली बॉर्डर) से मात्र पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतनी कम दूरी होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग अनिवार्य हो जाता है, जो संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों के ऊपर से गुजरता है। नेपाल की आपत्ति के बावजूद लिपुलेख-लिम्पियाधुरा मार्ग से भारत-चीन के बीच 2026 के सीजन में लगभग 1.46 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार हुआ। इसमें भारत से करीब 74.95 लाख रुपये का निर्यात और चीन से लगभग 75.51 लाख रुपये का आयात शामिल है। चीन ने भी नेपाली नेतृत्व को ऐसी आपत्ति से रोका था। बालेन्द्र शाह पर पुराने प्रधानमंत्रियों का दबाव था कि वे दिल्ली यात्रा के दौरान इस विवादित विषय को उठाएं। वर्ष 1950 की संधि की समीक्षा और पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के लंबित मुद्दों को उठाकर पूरी यात्रा की किरकिरी होनी थी। मोदी और बालेन्द्र की बंद कमरे में हुई बैठक ने इन मुद्दों को दरकिनार कर सूझबूझ का ही परिचय दिया।

यों, बालेन्द्र शाह ने कहा था कि सीमा पर अतिक्रमण एकतरफा नहीं है। नेपाल ने भी अनगिनत भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण या कब्जा किया है। जून, 2026 के अंत में नेपाली संसद में कही गई इस खरी बात से नेपाल में बहुत से नेताओं की भृकुटियां तन गई थीं। कोई पूछे कि बालेन्द्र शाह की दिल्ली यात्रा से नेपाल को क्या-क्या हासिल हुआ? भारत ने करीब 1.6 अरब डॉलर (15,000 करोड़ रुपये) का पैकेज घोषित किया। इसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचे के लिए 3,500 करोड़ रुपये का अनुदान तथा ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है। आठ सहमति-पत्रों के आदान-प्रदान के दौरान 'विकसित भारत और समुन्नत नेपाल' के लिए साझा विजन अपनाया गया। इनमें ऊर्जा, डिजिटल संपर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रेल कनेक्टिविटी, खेल और उपग्रह सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के गूढ़ार्थ को समझिए, 'भारत-नेपाल एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) की रिपोर्ट बीते दिनों की बात हो गई है। वर्तमान संदर्भ में यह 'अप्रासंगिक' है।'

फरवरी, 2016 में तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा के दौरान आठ सदस्यीय ईपीजी (प्रत्येक देश से चार-चार विशेषज्ञ) का गठन किया गया था। इसका मुख्य कार्य 1950 की भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि, सीमा विवाद (जैसे कालापानी), व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों की समीक्षा कर बदलते समय के अनुसार सुझाव देना था। वर्ष 2018 में रिपोर्ट तैयार तो हो गई, लेकिन उसका खुलासा दोनों में से किसी पक्ष ने नहीं किया। वह विवादों का एक पिटारा जैसी है!

लेखक जियो-पॉलिटिकल मामलों के पत्रकार हैं।

समझदारी से बचाव करना ताकत के बल पर मुकाबला करने से बेहतर है

एन. रघुरामन

दुनिया के ज्यादातर लोग इस गुरुवार जब थैंक्सगिविंग-डे पर जरूरतमंदों और भूखों को खाना खिलाने में जुटे थे, तब असम के गोलाघाट जिले के किसानों ने भी इस हफ्ते कुछ ऐसे भूखे मेहमानों का बुफे अरेंज किया, जो हमारी तरह एक प्लेट नहीं, बल्कि टनों में खाना खाते हैं। सोच रहे हैं कि ये टनों में खाना किसके लिए था?

यह जंगली हाथियों के लिए था। हाथियों के लिए फसल कटाई का मौसम त्योहार जैसा होता है। वे सिर्फ खाने की तलाश में निकलते हैं और नहीं जानते कि यह फसल किसने उगाई है। बाकी साल वे छोटे-छोटे झुंडों में घूमते रहते हैं।

यह सिर्फ उनके प्रति दयालुता नहीं, बल्कि अपनी फसलों को उन्हीं भूखे जानवरों से बचाने का समझदारी भरा तरीका भी था। नाम्बोर वन्यजीव अभयारण्य से सटे गांवों में किसानों ने खास तौर पर हाथियों के लिए 100 बीघा में धान उगाया। विचार सीधा था- हाथियों के झुंडों को खाने का वैकल्पिक स्रोत दिया जाए, ताकि वे आसपास के खेतों को नुकसान न पहुंचाएं।

इस पहल ने 90 गांवों के किसानों को 30 हजार बीघा (करीब 9 हजार एकड़) की फसल हाथियों से बचाकर काटने में मदद की। सोशल ग्रुप हाथी बंधु' के फाउंडर और कंजर्वेशनिस्ट बिनोद दुलु बोरा ने यह योजना तब बनाई, जब हाथियों के बार-बार हमलों के कारण ग्रामीणों ने खेत छोड़ दिए थे।

जानवरों से लड़ने के बजाय उन्होंने उस खाली जमीन को हाथियों का फीडिंग ग्राउंड बना दिया। केले की खेती से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो ग्रुप ने धान, एलिफेंट ग्रास और फलदार पेड़ लगाए।

यह सह-अस्तित्व का अनोखा रूप था- अपनी फसल बचाने के लिए उसी का पेट भरो, जिससे नुकसान का खतरा है। हमारे पूर्वज साल के हर दिन अपने सुंदर तरीके से थैंक्सगिविंग मनाते थे।

हर सुबह महिलाएं घरों के बाहर चावल के आटे से रंगोली बनाती थीं, केमिकल कलर्स से नहीं। यह महज मेहमानों के स्वागत या समृद्धि लाने की सजावटी परंपरा नहीं थी, बल्कि प्रकृति के सूक्ष्मतम जीवों को न्योता भी होता था।

चींटियां और छोटे कीड़े उस आटे से



अपना हिस्सा लेते और रोजमर्रा के काम में लग जाते थे। चींटियां मिट्टी में सुरंगें और छोटे रास्ते बना कर उसमें हवा-पानी का संचार बेहतर करने में मदद करती हैं।

घर की साधारण परंपरा लगने वाला यह काम असल में प्रकृति का आभार जताने का तरीका था, जो सुनिश्चित करता कि छोटे से छोटा जीव भी भूखा न रह जाए। हमारे पूर्वज थैंक-यू कहने के लिए नवंबर के किसी खास दिन का इंतजार नहीं करते थे। वे हर सुबह मुट्ठी भर आटे, थोड़ी-सी दया और इस गहरी समझ के साथ थैंक्सगिविंग मनाते थे कि हम अनगिनत जीवों के साथ इस धरती को साझा करते हैं। जंगलों की विनाशकारी आग को रोकने के लिए दुनियाभर में फॉरेस्ट मैनेजर इतना ही अनोखा और थोड़ा मॉडर्न एक तरीका अपनाते हैं, जिसे प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग' या बैक-बर्निंग' कहते हैं। विचार सुनने में अजीब लगता है- एक आग रोकने के लिए जानबूझकर दूसरी आग लगाना। कल्पना कीजिए जंगल की आग किसी बस्ती की ओर बढ़ रही है।

फायरफाइटर्स बढ़ती आग से आगे कुछ दूरी पर एक उपयुक्त जगह चुनते हैं। मौसमी परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए वे पहले से बनाई गई कंट्रोल-लाइन के किनारे वनस्पति में आग लगाते हैं। यह छोटी आग सूखी घास, पत्तियों, झाड़ियों और दूसरी ऐसी चीजों को जला देती है, जो आगे बढ़ती जंगल की आग को और भड़का सकती थीं।

फिर फायरफाइटर्स पानी और अन्य तरीकों से इस नियंत्रित आग को बुझा देते हैं। जब मुख्य आग वहां पहुंचती है तो वह मंद पड़ जाती है या उसका आगे बढ़ना रुक जाता है।

ये उदाहरण हमें सिखाते हैं कि हर समस्या की कोई वजह और हर टकराव का कोई ट्रिगर होता है। ताकत के बल पर नतीजों से लड़ने के बजाय यह समझें कि समस्या को बढ़ावा क्या दे रहा है और उसी जड़ पर काम किया जाए।

फंडा यह है कि कभी-कभी थोड़ी-सी शेयरिंग, दयालुता का छोटा-सा काम या सोचा-समझा दखल किसी बहुत बड़ी मुसीबत को टाल सकते हैं। असली समझदारी प्रकृति को हराने में नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर रहने का तरीका सीखने में है।

नई दृष्टि दे सकते हैं राजनीतिक-ऐतिहासिक प्रसंग

विश्वनाथ सचदेव

हर बात राजनीति का औज़ार नहीं होती, हर आत्मीयता अश्लील नहीं होती और पति-पत्नी का आपसी लगाव कोई अपराध नहीं होता। आवश्यकता राजनीति के चक्रव्यूह से उबरकर चीज़ों को देखने और समझने की है।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बहुचर्चित आत्मकथा 'बिलोंगिंग : अ जर्नी ऑफ लव' को मैं भी अभी तक पूरा नहीं पढ़ पाया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं हमारे समय के एक बड़े और महत्वपूर्ण कालखंड को समेटने वाली इस पुस्तक को पढ़ना नहीं चाहता। दरअसल, जिस तेज़ी से देश-विदेश में लगभग साढ़े पांच सौ पृष्ठों की यह किताब पढ़ी गई और जिस तरह इसे लेकर विवादों और वाद-विवाद का दौर चला, उससे ऐसा लगता है कि शायद ही इसकी कोई महत्वपूर्ण बात बची हो, जो जनता की जानकारी में न आई हो। टुकड़ों-टुकड़ों में इसके विभिन्न अंशों को समझने-समझाने की जितनी कोशिशें हुईं, उसके बाद यही आभास होता है।

परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। निश्चित रूप से सोनिया गांधी की यह संस्मरणात्मक आत्मकथा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह मात्र सोनिया गांधी की कहानी नहीं है, बल्कि उस परिवार की गाथा भी है, जिसने हमारी आज़ादी की लड़ाई में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद देश के निर्माण में भी जिसकी निर्णायक भूमिका रही। इसमें निश्चित रूप से बहुत कुछ ऐसा होगा, जो हमारे लिए अनजाना है और जिसे हमें जानना चाहिए। इस सबके लिए इस पुस्तक को पढ़ना आवश्यक है और मैं भी इसे ज़रूर पढ़ूंगा।

लेकिन, इस पुस्तक को पढ़ने वाले बहुत से पाठक जिस तरह के मुद्दों को चर्चा का विषय बना रहे हैं, वह थोड़ा चौंकाने वाला है। ऐसा ही एक मुद्दा सोनिया गांधी के अपने पति राजीव गांधी की गोद में बैठकर खाना खाने का है। सोनिया ने अपनी किताब में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है; यह प्रसंग तो पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर राहुल गांधी ने बड़ी ही मासूमियत के साथ साझा किया था। इसे उसी मासूमियत के साथ समझने की कोशिश होनी चाहिए थी, पर जो कुछ होते हुए दिख रहा है, वह किसी भी प्रकार से आश्वस्त करने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो साढ़े पांच सौ पृष्ठों की किताब से मिलने वाली जानकारी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण राहुल गांधी द्वारा दी गई यह एक जानकारी बन गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के आलोचकों के हाथ जैसे कोई खज़ाना लग गया हो। सोनिया गांधी ने इसे 'अ जर्नी ऑफ लव' (प्यार की यात्रा) नाम दिया है, लेकिन लोग उनकी इस पूरी यात्रा को राहुल गांधी के एक वाक्य के चश्मे से देखने में लगे हैं। मैंने इस पुस्तक के बारे में जितना भी पढ़ा और जाना है, उससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है, जिस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। यह केवल एक महिला के संस्मरणों का गुलदस्ता नहीं है, बल्कि देश के एक ऐसे परिवार की कथा है, जिसने समाज और राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि इस योगदान ने देश को कैसे और कितना प्रभावित किया। पुस्तक के राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रसंग हमारे समय के इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। आपातकाल, ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख दंगों जैसे संवेदनशील विषयों पर गांधी परिवार के पक्ष को समझने



में सोनिया गांधी की जानकारियां और टिप्पणियां सहायक हो सकती हैं। यदि यह गांधी परिवार के बचाव की कोशिश भी है—जैसा कि कांग्रेस के विरोधी कह रहे हैं—तब भी इस पक्ष को समझना ज़रूरी है। सोनिया गांधी ने स्वयं कहा है कि अपने परिवार के बारे में फैली कई अवास्तविक और मिथ्या बातों का खंडन करने के लिए उन्होंने यह संस्मरण लिखा है।

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि सात समंदर पार करके अपने प्रियतम के देश आने के लिए इटली की एक युवती ने अपने आप से और अपने आसपास के माहौल से कितना और कैसा संघर्ष किया। एक बिल्कुल अलग समाज और वातावरण में पली-बढ़ी युवती कैसे एक भारतीय बहू बन गई, यह समझना उससे जुड़े कई सवालों का जवाब बन सकता है। इस बात को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि एक नए देश को अपना बनाना, अपने स्वभाव के विपरीत जाकर सार्वजनिक जीवन को अपनाना तथा एक परिवार, समाज और राजनीतिक पार्टी को संभालना किसी भी व्यक्ति के लिए सहज नहीं हो सकता। पुस्तक के कई पाठकों का मानना है कि सोनिया गांधी की रीति-नीति से असहमति के बावजूद, इसमें दी गई जानकारी समय और समाज को समझने में बेहद मददगार है। इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री पद को ठुकराकर और कांग्रेस पार्टी को बचाने की कवायद में सोनिया गांधी ने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया।

पर दुर्भाग्य से, इन गंभीर विषयों पर विमर्श होने के बजाय हल्के-फुल्के प्रसंगों पर जिस प्रकार चटखारे लिए जा रहे हैं, वह इस बात का एहसास कराता है कि कहीं न कहीं कुछ चूक हो रही है। इटली के एक छोटे-से शहर में जन्मी-पली एक युवती भारत आकर किस तरह भारतीय बनती है, यह सवाल भीतर तक झकझोरने वाला है। दशकों तक यह सारी कहानी एक रहस्यमय पर्दे में छिपी रही और अब इस किताब के माध्यम से वह पर्दा उठा है। इससे जो दृश्य सामने आता है, वह एक सीमा तक विचलित भी कर सकता है, पर कुल मिलाकर कई सवालों का समाधान भी प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक आज के भारत की राजनीति को समझने-समझाने का एक अवसर भी देती है, लेकिन इस पर उस गंभीरता से विचार नहीं हो रहा है, जैसा होना चाहिए था।

इस किताब से एक और बेहद मार्मिक घटना की जानकारी मिलती है, जो इलाहाबाद (प्रयागराज) से जुड़ी है। सोनिया गांधी ने बताया है कि यह 1970 की बात है, जब इंदिरा गांधी अपनी बहू को अपना पैतृक घर 'आनंद भवन' दिखाने के लिए इलाहाबाद ले गई थीं। वहीं इंदिरा जी ने सोनिया को बताया कि परिवार के दिवंगत सदस्यों की अस्थियां प्रवाहित करनी हैं। उन्होंने राजीव और संजय को अपने पिता, माता और दादा की अस्थियां संगम में विसर्जित करने के लिए कहा और इस बात का विशेष ध्यान रखा कि इस पूरे कार्य में सोनिया भी सम्मिलित रहें। इस सहज और अपनेपन से भरे पल के बारे में सोनिया ने अपनी किताब में लिखा है, 'मैं इस किस्मत पर हैरान भी थी, जो मुझे एक दूर देश से, पृथक लोगों और पृथक परिस्थितियों से इस पवित्र और अत्यंत करीबी रस्म में हिस्सा लेने के लिए वहां ले आई थी।' यह छोटी-सी घटना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सोनिया को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर जहां इंदिरा गांधी ने अपनी विदेशी पुत्रवधू को भारतीय समाज की अनवरत परंपरा से जोड़ दिया, वहीं सोनिया के भीतर भी यह भाव जगाया कि वह अब पूरी तरह भारतीय बनती जा रही हैं।

ऐसी ही संवेदनशील बातों पर चर्चा होनी चाहिए, पर हो नहीं रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी ने अपने माता-पिता के सहज स्नेह की बात को सार्वजनिक क्यों किया। इस बात को राहुल गांधी के बचपने का उदाहरण बताने वालों को यह समझना चाहिए कि हर बात राजनीति का औज़ार नहीं होती, हर आत्मीयता अश्लील नहीं होती और पति-पत्नी का आपसी लगाव कोई अपराध नहीं होता। शिव-पार्वती का उदाहरण देकर अपना बचाव करने की राहुल गांधी को कोई आवश्यकता नहीं है; आवश्यकता राजनीति के चक्रव्यूह से उबरकर चीज़ों को देखने और समझने की है। यहां गुलज़ार की यह पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है—'प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो।'

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

रिसाली महापौर ने अतिरिक्त कक्ष का किया लोकार्पण

रिसाली। रिसाली महापौर शशि सिन्हा वार्ड 17 स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरोदा में बने अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण की। उन्होंने इसके लिए 10 लाख की राशि अपने निधि से स्वीकृत की थी। महापौर ने फीता काटकर कक्ष का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महापौर शशि सिन्हा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा शहर की विकास पर रहा है। यही वजह है कि उन्होंने विद्या के मंदिर में आने वाले भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को समझा और अतिरिक्त कक्ष के लिए राशि स्वीकृत की। इस दौरान महापौर शशि सिन्हा ने विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से चर्चा की। महापौर का स्वागत स्कूल के शिक्षक व विद्यार्थियों ने किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से महापौर परिषद के सदस्य जमुना ठाकुर व वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे।

8 से 11 दिसंबर तक खुली संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली प्रतिष्ठित खुली संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 8 से 11 दिसंबर 2026 तक महात्मा गांधी कला मंदिर, सिविक सेंटर, भिलाई में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में कर्नाटक संगीत (सुगम एवं शास्त्रीय गायन), हिंदुस्तानी संगीत (सुगम एवं शास्त्रीय गायन), लोक गायन, एकल नृत्य (भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक एवं ओडिसी), हिंदुस्तानी वाद्य संगीत (तंतु वाद्य एवं ताल वाद्य) तथा खुली आयु वर्ग समूह नृत्य स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा।प्रतियोगिता के लिए आयु समूह को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें 6 से 12 वर्ष तथा 13 से 18 वर्ष के प्रतिभागी शामिल हो सकेंगे। प्रतिभागी अधिकतम दो विधाओं में ही भाग ले सकते हैं।

वित्त एवं लेखा विभाग में राजभाषा कार्यशाला का आयोजन

भिलाई। बीएसपी के वित्त एवं लेखा विभाग में राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन एवं कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यपालक निदेशक प्रवीन निगम तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य महाप्रबंधक आर. के. भट्टाचार्जी उपस्थित थे। कार्यक्रम में महाप्रबंधक आशीष कुमार अग्रवाल एवं उप महाप्रबंधक राघवेन्द्र कुमार गर्ग सहित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि प्रवीन निगम ने अपने संबोधन में कहा कि राजभाषा कार्यशालाओं को केवल संवैधानिक वांछनीयता तक सीमित न रखते हुए हिंदी में कार्यालयीन कार्य करना अपनी प्राथमिकता और आदत बनाना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी में हस्ताक्षर करने की शुरुआत करते हुए दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

संविधान दिवस पर दुर्ग जिले के न्यायालयों एवं विधि महाविद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन

श्रीकंचनपथ न्यूज



दुर्ग। भारतीय संविधान के अंगीकरण की स्मृति में आज संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के तत्वावधान में जिले के विभिन्न न्यायालयों, विधि महाविद्यालयों एवं अन्य स्थानों पर संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन तथा विधिक जनजागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता के मूल आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के. विनोद कुजूर तथा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार भागवतकर की विशेष उपस्थिति में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। कार्यक्रम में न्यायाधीशगण एवं युवा अधिवक्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विशेष रूप से युवा अधिवक्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने संविधान के प्रति उनकी आस्था, विधि के शासन के प्रति प्रतिबद्धता तथा न्यायिक व्यवस्था के मूल्यों के प्रति सम्मान को प्रदर्शित किया।

इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत की अध्यक्ष श्रीमती सुषमा लकड़ा की विशेष उपस्थिति में भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया तथा संविधान में निहित मूल आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

इसी क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत के न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों में भी संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया तथा संविधान में निहित मूल आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

महापौर ने विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर कार्यों को शीघ्र शुरू करने के दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। शहर में चल रहे विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर महापौर अलका बाघमार ने अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा, भवन अधिकारी प्रकाश चंद थवानी, सहायक अभियंता गिरीश दीवान, संजय ठाकुर, हरिशंकर साहू, पंकज साहू, मोहित मरकाम, अपर्णा मिश्रा, भारती ठाकुर एवं विकास दमाहे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



महापौर ने विभागवार विकास एवं निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, कार्यों की प्रगति, पूर्णता की समय-सीमा तथा कार्यों में आ रही बाधाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से स्वीकृत लेकिन अब तक प्रारंभ नहीं हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शीघ्र पूर्ण कर अप्रारंभ कार्यों को तत्काल शुरू कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ धरातल पर उतारा जाए।

महापौर ने कहा कि शहर में सड़क, नाली, पुलिया, भवन, उद्यान एवं अन्य अधोसंरचना संबंधी कार्य नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं और शहर के विकास से सीधे जुड़े हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने दिया जाए। जिन कार्यों की गति धीमी है, उनमें संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर तेजी लाएं और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करें,उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता तथा निर्धारित तकनीकी मापदंडों का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी विकास एवं निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण हों, ताकि नागरिकों को लंबे समय तक बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

बैठक में लोक कर्म विभाग, जल कार्य विभाग, जल विभाग, अधोसंरचना एवं 15वें वित्त आयोग सहित विभिन्न मदों से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गई। महापौर ने चल रहे कार्यों, पूर्ण हो चुके कार्यों तथा आगामी कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, पाइपलाइन विस्तार एवं जल संबंधी नागरिक समस्याओं पर भी चर्चा की।

महापौर ने जल विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के साथ पाइपलाइन से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन विस्तार, सुधार अथवा अन्य आवश्यक कार्य किए जाने हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि नागरिकों को पेयजल संबंधी परेशानी न हो।

महापौर ने कहा कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और नागरिकों से प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें,बैठक के अंत में महापौर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत विकास कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारें, चल रहे कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करें तथा प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करें।

पारदर्शी उर्वरक वितरण हेतु एफएफएस मोबाइल ऐप एवं टोकन प्रणाली पर कृषक प्रशिक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। रबी सीजन 2026-27 में किसानों को समय पर, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने तथा कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से जिले में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल मोबाइल एप आधारित टोकन व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत किसानों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ना और उर्वरक प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाना है। जिले में एफएफएस टोकन वितरण की कार्यप्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा किसानों को इसके माध्यम से खाद क्रय करने की प्रक्रिया समझाने के लिए अब तक 362 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ग्राम स्तर पर आयोजित शिकसान चौपालश् के माध्यम से लगभग 5,600 कृषकों सहित सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु केवल योजना की सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं दी गई, बल्कि उन्हें स्वयं अपने मोबाइल से एफएफएस टोकन जनरेट करने और उसके माध्यम से उर्वरक प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया का प्रत्यक्ष (लाइव) प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। इससे किसान डिजिटल व्यवस्था को आसानी से समझ सकेंगे और खाद खरीदी के दौरान होने वाली भीड़भाड़ व अन्य संभावित परेशानियों से बच सकेंगे। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तरीय नोडल अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर्स, विकासखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स और मैदानी अमले द्वारा प्रत्यक्ष संवाद कर किसानों व विक्रेताओं को टोकन जनरेट करने की बारीकियों तथा आवश्यक सावधानियों से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त, जिले में संचालित खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत आयोजित ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी किसानों को कृषि विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ एफएफएस टोकन प्रणाली की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। अथवा नजदीकी सेवा सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से टोकन जनरेट कर सकते हैं।

श्रमिकों का आधार आधारित ई-केवाईसी एवं अभिलेख अद्यतन कार्य जारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। जिले में पंजीकृत श्रमिकों के अभिलेखों को आधार कार्ड के अनुरूप अद्यतन करने का कार्य लगातार जारी है। श्रम विभाग द्वारा ई-केवाईसी एवं आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से पात्र श्रमिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 669 शिविर आयोजित कर 27,718 पंजीकृत श्रमिकों के श्रम पंजीयन कार्ड को आधार कार्ड के अनुरूप अद्यतन करने के आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं।

सहायक श्रमायुक्त से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में 1 लाख 14 हजार 36 श्रमिकों का नया पंजीयन लंबित नहीं है, बल्कि ये सभी पूर्व से पंजीकृत श्रमिक हैं, जिनके पंजीयन अभिलेखों का आधार कार्ड से मिलान एवं आवश्यक अद्यतन किया जा रहा है। शासन द्वारा दोहरे एवं अपात्र पंजीयन रोकने, योजनाओं में पारदर्शिता लाने तथा पात्र श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। पुराने पंजीयन अभिलेखों में नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, पता एवं मोबाइल नंबर में अंतर होने के कारण कुछ मामलों में ऑनलाइन सत्यापन में समय लग रहा है। ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिए विभाग द्वारा तकनीकी सहायता एवं संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, लोक सेवा केंद्रों एवं च्वाइस सेंटरों के माध्यम से प्रचार-प्रसार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय वार्डों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

श्रम विभाग के अनुसार मंडल गठन से अब तक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 3 लाख 91 हजार 883 श्रमिकों को 1 अरब 25 करोड़ 75 लाख 59 हजार 147 रुपये तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 57 हजार 263 श्रमिकों को 53 करोड़ 53 लाख 52 हजार 692 रुपये की सहायता प्रदान की गई है। वहीं पिछले तीन वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के 26 हजार 551 श्रमिकों को 59 करोड़ 19 लाख 43 हजार 750 रुपये से लाभान्वित किया गया है। जिन श्रमिकों के पंजीयन कार्ड अद्यतन हो चुके हैं।

सीएसआर-बीएसपी की पहल से दुर्ग जिले के चार गांवों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर, 182 ग्रामीण हुए लाभान्वित

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीएसपी-सीएसआर द्वारा दुर्ग जिले के चार गांवों में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल 182 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श के साथ निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। इस पहल के माध्यम से ग्रामीणों को उनके गांव में ही स्वास्थ्य जांच एवं प्राथमिक चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

ग्राम घुघुवा, ब्लॉक पाटन में आयोजित शिविर में बीएसपी-सीएसआर की ओर से डॉ. ज्योति सिन्हा, फार्मासिस्ट एम. जाह्नवी, नर्सिंग स्टाफ तृप्ति कुमारी एवं पंजीयन कार्य हेतु पायल पवार तथा जिला चिकित्सालय की सीएचओ रूबी वर्मा ने सेवाएं प्रदान कीं। इस शिविर में 30 पुरुष एवं 20 महिलाओं सहित कुल 50 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच कराई और निःशुल्क दवाइयां प्राप्त कीं।



इसी क्रम में ग्राम चिचा, ब्लॉक धमधा में आयोजित शिविर में डॉ. आलिया हुसैन, फार्मासिस्ट एम. जाह्नवी, नर्सिंग स्टाफ तृप्ति कुमारी एवं पंजीयन हेतु पायल पवार तथा जिला चिकित्सालय की सीएचओ मोना साहू ने सेवाएं प्रदान कीं। 15 पुरुष एवं 18 महिलाओं सहित कुल 33 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय परामर्श का लाभ उठाया।

वहीं, ग्राम डंडेसरा, ब्लॉक निकुम में आयोजित शिविर में बीएसपी-सीएसआर की ओर से डॉ. सबूरी कनौजिया, फार्मासिस्ट एम. जाह्नवी, नर्सिंग स्टाफ तृप्ति कुमारी एवं पंजीयनकर्ता पायल पवार तथा जिला चिकित्सालय के सीएचओ भोजकुमार देशमुख उपस्थित रहे। इस शिविर में 15 पुरुष एवं 36 महिलाओं सहित कुल 51 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच कराई तथा निःशुल्क दवाइयां प्राप्त कीं। इसी तरह ग्राम गोढ़ी, ब्लॉक धमधा में आयोजित शिविर में डॉ. नितिन कुमार महंत, फार्मासिस्ट मनीष कुमार देशमुख, नर्सिंग स्टाफ रेणुका वर्मा एवं पंजीयनकर्ता राकेश कुमार तथा जिला चिकित्सालय की सीएचओ (एफ) गुलेश्वरी साहू का विशेष सहयोग रहा। इस शिविर में 17 पुरुष एवं 31 महिलाओं सहित कुल 48 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय परामर्श का लाभ लिया।

दुर्ग जिले के इन चारों गांवों में आयोजित शिविरों के माध्यम से कुल 77 पुरुष एवं 105 महिलाओं सहित 182 ग्रामीण लाभान्वित हुए। बीएसपी-सीएसआर की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने तथा आमजन को स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श एवं आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने की दिशा में संयंत्र की सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल से दुर्ग शहर को मिली बड़ी सौगात

9.10 करोड़ रुपये से सड़कों और चौक-चौराहों का होगा कायाकल्प

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास और सुशासन का सिलसिला निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने सौगात मिली है। शिक्षा मंत्री एवं दुर्ग विधायक गजेन्द्र यादव के सतत प्रयासों से दुर्ग शहर के प्रमुख चौक-चौराहों एवं महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण, उन्नयन और सौंदर्यीकरण के लिए 9 करोड़ 10 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।



इस स्वीकृति से शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहों में शामिल पटेल चौक की तस्वीर बदलेगी। इसके साथ ही बस स्टैंड से पचरीपारा होते हुए गणेश मंदिर मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण सहित अन्य प्रमुख मार्गों का विकास किया जाएगा। इन कार्यों के पूरा होने से शहरवासियों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी और आवागमन पहले से अधिक सुविधाजनक एवं सुरक्षित होगा। दुर्ग शहर के प्रमुख एवं अत्यधिक व्यस्त पटेल चौक का चौड़ीकरण एवं उन्नयन किया जाएगा। इसके अंतर्गत चौक के चारों ओर चौड़ी सड़क, सर्विस रोड, डिवाइडर, आइलैंड, रेलिंग, फुटपाथ, नाली निर्माण, सौंदर्यीकरण एवं विद्युतीकरण के कार्य प्रस्तावित हैं। इससे चौक पर यातायात का दबाव कम होगा, वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित होगी और शहर के प्रमुख प्रवेश एवं संपर्क मार्गों पर आवागमन सुगम बनेगा। स्वीकृत हुए राशि से दुर्ग बस स्टैंड से पचरीपारा पहुंच मार्ग तथा पचरीपारा से गणेश मंदिर मार्ग में पानी टंकी तक के संकरे हिस्से का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही बस स्टैंड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स के पीछे की सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 14 मीटर तक करने का प्रस्ताव है। इन मार्गों के उन्नयन से शहर के प्रमुख व्यावसायिक एवं आवासीय क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होगा।

इन विकास कार्यों में केवल सड़क चौड़ीकरण ही नहीं, बल्कि नागरिक सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। फुटपाथ निर्माण से पैदल चलने वाले नागरिकों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। नाली निर्माण से जल निकासी बेहतर होगी तथा जलभराव की समस्या में कमी आएगी। वहीं, बेहतर प्रकाश व्यवस्था से रात के समय भी आवागमन सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। शिक्षा मंत्री एवं दुर्ग विधायक गजेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दुर्ग शहर को आधुनिक, सुव्यवस्थित और विकसित शहर बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। शहर की बढ़ती आबादी और यातायात की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सड़कों, चौक-चौराहों और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

Since 1972
CROWN®-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size

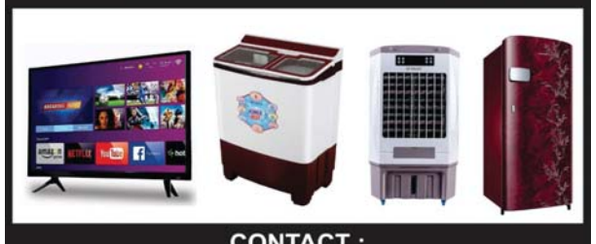

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास खबर

धान खरीदी के साथ किसानों के स्वास्थ्य की भी चिंता

रायपुर। राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ ही किसानों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जिला प्रशासन की इस संवेदनशील पहल के तहत किसानों को धान उपार्जन केन्द्रों में ही स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले के सभी 122 धान उपार्जन केन्द्रों में क्रमवार विशेष स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव जिले के चार उपार्जन केन्द्रों-कन्हारपुरी, कोहका, रतनभाठ और कोलिहापुरी में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में कुल 83 किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इन शिविरों में रक्तचाप, ब्लड शुगर एवं यूरिन की जांच के साथ आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। किसानों के साथ-साथ उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत हमालों और समिति के कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

4-5 दिसम्बर को होगा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव

रायपुर। प्रदेश के युवाओं की कला, संस्कृति और रचनात्मक प्रतिभाओं का संगम आगामी 4 दिसम्बर और 5 दिसम्बर को बिलासपुर के बहतराई स्थित स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में होगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में प्रदेश के सभी 33 जिलों से लगभग तीन हजार प्रतिभागी शामिल होंगे। महोत्सव के उद्घाटन एवं समापन समारोह आउटडोर स्टेडियम में प्रस्तावित हैं, जिनमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक आकांक्षा शिक्षा खलखो ने आज आयोजन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य मंच, अतिथियों एवं कलाकारों के ग्रीन रूम सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी तैयारियां 30 नवम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में लोकनृत्य, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, निबंध लेखन और पारंपरिक वेशभूषा सहित विभिन्न विधाओं में युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आउटडोर स्टेडियम के मुख्य मंच पर उद्घाटन एवं समापन समारोह के साथ सांस्कृतिक संध्या और लोकनृत्य का आयोजन होगा।

धान खरीदी को मिल रही गति रकबा समर्पण में भी किसान निभा रहे सक्रिय भागीदारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की किसान हितैषी एवं पारदर्शी धान उपार्जन व्यवस्था के तहत धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। किसान उत्साहपूर्वक अपनी उपज का विक्रय करने के साथ ही रकबा समर्पण की प्रक्रिया में भी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। धमतरी जिले में अब तक 10 हजार 196 किसानों से 3 लाख 55 हजार 257.60 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं 4,403 किसानों ने 209.87 हेक्टेयर रकबे का समर्पण कर सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था में अपना योगदान दिया है। खरीफविपणन वर्ष 2026-27 में धमतरी जिले के कुल 1 लाख 31 हजार 491 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। इनमें 77 हजार 603 सीमांत, 51 हजार 493 लघु तथा 2 हजार 395 दीर्घ कृषक शामिल हैं। अब तक धान का विक्रय करने वाले किसानों में 6 हजार 236 सीमांत, 3 हजार 721 लघु एवं 239 दीर्घ कृषक शामिल हैं।

करमा महोत्सव में 71.48 करोड़ रुपये के 694 विकास कार्यों की सौगात

हमारी सरकार जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के साथ दूरस्थ अंचलों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी, 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसान भी होंगे लाभान्वित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर हैं। करमा महोत्सव हमारी लोकआस्था, प्रकृति के प्रति सम्मान और सामाजिक एकजुटता का जीवंत प्रतीक है। हमारी सरकार इन गौरवशाली परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ प्रदेश के दूरस्थ और जनजातीय अंचलों में विकास की नई संभावनाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ हर गांव, हर परिवार और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।





मुख्यमंत्री साय बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत रघुनाथनगर के शासकीय हाई स्कूल मैदान में आयोजित करमा महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने जिलेवासियों को 71 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत के 694 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 54 करोड़ 21 लाख रुपये के 672 कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास तथा 17 करोड़ 27 लाख रुपये के 22 कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

मुख्यमंत्री ने करमा देव को नमन करते हुए क्षेत्रवासियों को करमा महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री साय ने क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने वाड्रफनगर में उप पंजीयक कार्यालय भवन के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही ग्राम पंचायत रघुनाथनगर एवं बरतीकला में मंगल भवन निर्माण, ग्राम पंचायत महेवा में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रकसगंडा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित एवं भूमिपूजन किए गए प्रमुख कार्यों में भगवानपुर से मेंढ़ारी तथा डिण्डो-विमलापुर-नावाडीह सड़क निर्माण, सात नल-जल योजनाएं, रामानुजगंज अस्पताल में डायलिसिस यूनिट, 12 आंगनबाड़ी भवन, राजपुर में एसडीएम कार्यालय भवन तथा चान्दो में तहसील कार्यालय भवन सहित अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्य शामिल हैं। इन कार्यों से क्षेत्र में सड़क संपर्क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण प्रदेश की समृद्धि का आधार है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से 68 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। यह योजना महिलाओं के जीवन में आर्थिक सुरक्षा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का नया आधार बनी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में जिला प्रशासन की अभिनव पहल 'वृद्धजन क्लिनिक' का शुभारंभ किया। 'स्वस्थ वृद्ध, खुशहाल जीवन' के ध्येय के साथ शुरू किए गए इस क्लिनिक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पंजीयन काउंटर, चिकित्सकीय जांच और विशेषज्ञ परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। क्लिनिक में जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी, इन्फ्रारेड थेरेपी, मसाज चेयर तथा आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत शिरोधारा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस पहल से बुजुर्गों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें एक ही छत के नीचे समुचित देखभाल मिल सकेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर की सराहना करते हुए कहा कि दूरस्थ अंचलों में लोगों, विशेषकर महिलाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यंत सराहनीय प्रयास है।

उन्होंने सेवाभाव से कार्य कर रहे सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। शिविर में पहुंची महिलाओं ने भी घर के समीप विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया।

सरगुजा सांसद श्री चिंतामणी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ दूरस्थ अंचलों तक पहुंच रहा है और महिलाओं एवं युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विकास को नई गति मिली है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अधोसंरचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में पूर्व गृहमंत्री एवं वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, संभागायुक्त सरगुजा नरेन्द्र दुग्गा, आई जी सरगुजा रेंज दीपक झा, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरामुनि निकुंज, जनपद पंचायत वाड्रफनगर की अध्यक्ष श्रीमती शशि सिंह पोर्ते सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

किसानों की खुशहाली हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान करती है और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। प्रदेश में किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए इस वर्ष 360 नए धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिन किसानों की उपज प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम है, उन्हें भी पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा और खेती को लाभकारी बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

'बालभोग' नवाचार से बच्चों के पोषण में सुधार का प्रयास

कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जिले में संचालित विकास कार्यों और नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनवरी 2012 में गठित बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। जिला प्रशासन का विशेष ध्यान दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने पर है। उन्होंने बताया कि बच्चों में कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से जिले में 'बालभोग' नवाचार प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाएं रागी, सत्तू और श्रीअन्न से पौष्टिक लड्डू तैयार करती हैं। पोषण सखियां घर-घर पहुंचकर कुपोषित बच्चों को अपने सामने इनका सेवन कराती हैं तथा बच्चों की पोषण संबंधी प्रगति का नियमित रिकॉर्ड संधारित करती हैं। यह पहल पोषण सुधार के साथ ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता को भी बढ़ावा दे रही है।

श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना विभाग की पहली प्राथमिकता

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश के श्रम, वाणिज्य एवं उद्योग तथा वाणिज्यिक कर मंत्री लखनलाल देवांगन ने श्रम विभाग की विभागीय बैठक लेकर जिलावार एवं योजनावार प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रमिकों के कल्याण में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी व जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ दिलाना विभाग की पहली प्राथमिकता है। श्रम मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गम्भीरता दिखाएं और बेहतर प्रदर्शन करें।

महानदी मंत्रालय के भूतल स्थित समिति कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री ने आगे कहा कि श्रमिकों के कल्याण व उनके हितों की रक्षा किस तरह से हो, इस पर अधिकारियों को विचार मंथन करने की आवश्यकता है और इसके लिए अधिकारी पूरी शिद्दत और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करें। साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने जिलों से आए श्रम अधिकारियों को पंजीयन के उपरांत पात्रतानुसार अधिकांश योजनाओं का लाभ श्रमिकों को दिलाने तथा उद्योगों का नियमित निरीक्षण कर आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।



श्रम विभाग के सचिव एवं श्रम आयुक्त श्री हिमशिखर गुप्ता ने पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी 33 जिले से आए श्रम अधिकारियों की योजनावार समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ई-केवायसी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011, ऑनलाइन रैण्डम निरीक्षण, विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतें एवं उनका निराकरण, बस्तर मुन्ने व नियद नेल्ला नार योजना 2.0 में विभागीय प्रगति, श्रम अन्न योजना के तहत संचालित केन्द्रों की स्थिति तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से संबंधित बिंदुओं पर सिलसिलेवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मैं स्वयं किसान का बेटा हूं, खेती की कठिनाइयों और अन्नदाता की जरूरतों को भलीभांति समझता हूं: मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ न्यूज

छत्तीसगढ़ में किसानों को मिल रहा देश में सर्वाधिक लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य देने के साथ ही धान खरीदी की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को भी निर्धारित सीमा तक अंतर की राशि का लाभ दिया जाएगा। इससे कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को भी आर्थिक लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री साय पत्रकारों से चर्चा के दौरान धान खरीदी और किसानों को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ के किसानों को जिस प्रकार आर्थिक लाभ दिया जा रहा है, वैसा लाभ किसी अन्य राज्य के किसानों को नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। धान खरीदी की व्यवस्था ऐसी हो कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और अधिकतम



सुविधाएं उन्हें घर बैठे मिल सकें, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं होता। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में खेती की परिस्थितियां और उत्पादन क्षमता भी अलग-अलग हैं। ऐसे में कम उत्पादन करने वाले किसानों को भी निर्धारित सीमा तक अंतर की राशि का लाभ देने का निर्णय उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं किसान का बेटा हूं और खेती-किसानी की परिस्थितियों को भलीभांति समझता हूं। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, उन्हें भी 21 क्विंटल की निर्धारित सीमा तक अंतर की राशि उनके खातों में प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार चाहती है कि प्रदेश का कोई भी किसान कम उत्पादन के कारण इस लाभ से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है।

किसानों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिले, खेती लाभकारी बने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो, इसी उद्देश्य से सरकार नीतिगत निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। धान खरीदी से लेकर आर्थिक सहायता और सुविधाओं के विस्तार तक हर स्तर पर किसानों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अन्नदाता की समृद्धि ही समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है।

खेल से मिलता है आत्मविश्वास, अच्छा स्वास्थ्य, अनुशासन, योग्यता और सम्मान: अरुण साव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने 'खेले बर आगू आहू सरगुजा के मान बढ़ाहू' के प्रेरक संदेश के साथ संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का भव्य शुभारंभ किया। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, युवाओं में अनुशासन एवं खेल भावना विकसित करने और स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देने के लिए आयोजित इस आयोजन में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बना। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक श्री प्रबोध मिंज और रामकुमार टोप्पो भी शुभारंभ समारोह में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरगुजा ओलंपिक



केवल खिलाड़ी तैयार करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित, आत्मविश्वासी और बेहतर इंसान बनाने का मंच भी है। इस वर्ष सरगुजा ओलंपिक के लिए 4 लाख 16 हजार 813 युवाओं ने पंजीयन कराया है, जो क्षेत्र में खेलों के प्रति बढ़ते उत्साह और जागरूकता को दर्शाता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरगुजा खेलों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और यहां की प्रतिभाएं अपनी पहचान बना रही हैं। श्री साव ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के माध्यम से खेलों के विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने हॉकी लीग का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वहीं स्पोर्ट्स साइंस और खेल अधोसंरचना के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिल सके।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। राज्य सरकार ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से भी खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप खेलों के क्षेत्र में भी अच्छी सुविधाएं विकसित की जा रही है। आने वाले समय में प्रदेश से और अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे।

श्री साव ने कहा कि खेल के मैदान से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। खेल से आत्मविश्वास, अच्छा स्वास्थ्य, अनुशासन, योग्यता और सम्मान मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में खेल को शामिल करना चाहिए और नियमित रूप से खेल मैदान में पसीना बहाना चाहिए।

उन्होंने घोषणा की कि सरगुजा में शीघ्र ही खेल अकादमी प्रारंभ की जाएगी, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकेंगे। संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक के शुभारंभ के साथ ही जशपुर और बलरामपुर की टीमों के बीच रस्साकसी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसने मैदान में उत्साह का माहौल बना दिया। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों की खेल उपलब्धियां हम सभी के लिए गर्व और सम्मान का विषय हैं।

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131





अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी



JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बेंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

ट्विंकल ने अक्षय कुमार को करण के शो में मुफ्त में जाने पर कही ये बात



कॉफी विद करण 9 में अक्षय कुमार खास मेहमान बनकर शामिल हुए। इस दौरान शो के कॉल अ स्टार सेगमेंट में करण जौहर ने अक्षय से उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को फोन करने के लिए कहा। दोनों के बीच हुई बेबाक बातचीत ने अब सबका ध्यान खींचा है। दरअसल, ट्विंकल ने करण के चैट शो में मुफ्त में शामिल होने को लेकर अक्षय पर मजाकिया अंदाज में तंज कसा।

अक्षय ने अपनी पत्नी ट्विंकल को फोन लगाया। बातचीत के दौरान, ट्विंकल ने बताया कि वह अक्षय के शो में आने के बारे में पहले ही करण से बात कर चुकी थीं।

उन्होंने अपने पति से कहा, मेरी कल ही करण से बात हुई थी। फिर उन्होंने आगे कहा, उन्होंने मुझसे रैपिड फायर राउंड को जज करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप आज इसमें शामिल हो रहे हो।

हालांकि, ट्विंकल की अगली बात ने बातचीत को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका फोन स्पीकर पर है और शो के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है। उन्होंने कहा, आप मुफ्त में काम कर रहे हैं, मुझे तो हैरानी हो रही है। करण ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा, सच में? तो क्या आपको हर चीज के लिए पैसे चाहिए? इस पर ट्विंकल चौंककर बोलीं, अरे, वो भी सुन रहे हैं।

करण ने इसके बाद मजाक में उनसे पूछा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि कॉफी विद करण में आने के लिए मुझे आपके पति को पैसे देने चाहिए?

उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि यह बातचीत शो के एपिसोड में शामिल होगी, उन्होंने ट्विंकल से कहा कि वह अभी ऑन एयर हैं और वह इस बातचीत को शो से नहीं हटाएंगे।

अब ट्विंकल की इस बात को सुनकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।



अल्लू अर्जुन की फिल्म राका से दक्षिण सिनेमा में डेब्यू करेंगे गोविंदा



एटली की आगामी साइंस-फिक्शन एक्शन फिल्म राका को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 90 के दशक के मशहूर अभिनेता गोविंदा भी इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकते हैं।

बताया जा रहा है कि फिल्म में गोविंदा की दिखाई देने की कुल अवधि भले ही कम हो, लेकिन कहानी में उनका किरदार काफी अहम होगा।

सूत्रों के हवाले से आई एक रिपोर्ट में इस कास्टिंग का जिक्र किया गया है। हालांकि, न तो फिल्म के निर्माताओं, न ही गोविंदा और न ही उनकी टीम ने इस खबर की आधिकारिक पुष्टि की है। उनके किरदार को लेकर भी फिलहाल कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।

अगर यह खबर सही साबित होती है, तो यह दक्षिण भारतीय सिनेमा में गोविंदा की पहली फिल्म होगी।

एटली राका का निर्देशन कर रहे हैं। इस फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आ सकते हैं।

अल्लू और दीपिका के अलावा, मृणाल ठाकुर, जाह्नवी कपूर और रश्मिका मंदाना के भी इस फिल्म का हिस्सा होने की चर्चा है।

खबर है कि राम्या कृष्णन, योगी बाबू और जिम सर्भ को भी अहम किरदारों के लिए चुना गया है।



किंग दोहराएगी शाहरुख खान का 20 साल पुराना रिकॉर्ड? सिनेमाघर में मचेगा धमाल

किंग के साथ शाहरुख खान की वापसी को लेकर दर्शकों के बीच जश्न का माहौल बना हुआ है। 2023 में आखिरी बार पठान, जवान और डंकी से दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद, अभिनेता अपनी अगली एक्शन थ्रिलर लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।

जैसे-जैसे फिल्म अपनी रिलीज के करीब आ रही है, इसके प्रति लोग बेताब होते जा रहे हैं। अब खबर है कि किंग अपनी अवधि के जरिए शाहरुख के 20 साल पुराने इतिहास को दोहराती दिखेगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख की किंग पूरे 3 घंटे 17 मिनट लंबी होने वाली है।

आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन अगर यह रनटाइम सही निकला तो यह 20 सालों में शाहरुख की पहली बड़ी फिल्म बन जाएगी जो 3 घंटे का आंकड़ा पार करेगी।

पिछली बार 2006 में रिलीज कभी अलविदा न कहना उनकी 3 घंटे से ज्यादा लंबी फिल्म थी, जिसमें रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा भी मौजूद थे।

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही किंग शाहरुख के 3 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी का प्रतीक है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी खुद उन्होंने अपनी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के जरिए उठाई है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान भी हैं। पिता-बेटी की जोड़ी को पर्दे पर पहली बार एक साथ देखना उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा।

फिल्म 24 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर सिनेमाघरों में आएगी।

कंडीशनर खरीदने से पहले इन पांच बातों का रखें ध्यान मिलेगा सही विकल्प

शैंपू के बाद बालों की देखभाल के लिए कंडीशनर का उपयोग किया जाता है। यह बालों को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है। हालांकि, बाजार में कई तरह के कंडीशनर उपलब्ध हैं, जिससे सही का चयन करना मुश्किल हो सकता है। आइए आज हम आपको कंडीशनर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं ताकि आपके बालों को सही देखभाल मिल सके और वे स्वस्थ रहें।

बालों के प्रकार को समझें

कंडीशनर खरीदते समय सबसे पहले अपने बालों के प्रकार को समझना जरूरी है।

अगर आपके बाल सूखे हैं तो नमी देने वाला कंडीशनर चुनें, जो बालों को नमी प्रदान करेगा, वहीं अगर आपके बाल तैलीय हैं तो हल्का और तेल नियंत्रण वाला कंडीशनर बेहतर रहेगा।

इसके अलावा अगर आपके बाल कमजोर हैं तो प्रोटीन युक्त कंडीशनर का चयन करें, जो बालों को मजबूती देगा और उन्हें स्वस्थ बनाएगा।

प्राकृतिक तत्वों का चयन करें

कंडीशनर में प्राकृतिक तत्वों का चयन करना हमेशा फायदेमंद होता है। जैसे कि एलोवेरा, नारियल तेल, आर्गन तेल आदि तत्व बालों को पोषण देते हैं और उन्हें स्वस्थ बनाए रखते हैं।

इनसे बने कंडीशनर न केवल बालों को मजबूती देंगे, बल्कि उन्हें चमकदार भी बनाएंगे।

इसके अलावा ये कंडीशनर बालों को हाइड्रेटेड रखते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं। इसलिए जब भी आप कंडीशनर खरीदें तो उसमें प्राकृतिक तत्वों की मौजूदगी पर खास ध्यान दें।

पैराबेन और सल्फेट से बचें

पैराबेन और सल्फेट वाले कंडीशनर से बचना चाहिए क्योंकि ये रसायन बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

पैराबेन एक संरक्षक होता है, जो लंबे समय तक शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सल्फेट एक सफाई करने वाला तत्व होता है, जो बालों को सूखा सकता है। इसलिए इनसे मुक्त कंडीशनर का चयन करें ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें और उनकी प्राकृतिक नमी बरकरार रहे। इनसे बालों की चमक भी बनी रहती है।

खुशबू पर दें ध्यान

कंडीशनर की खुशबू भी अहम होती है क्योंकि यह आपके बालों को ताजगी भरा एहसास दिलाती है।

हालांकि, बहुत तेज खुशबू वाले कंडीशनर से बचें क्योंकि इनमें कृत्रिम सुगंध हो सकती है, जो त्वचा पर असर डाल सकती है।

बेहतर होगा कि आप हल्की खुशबू वाले या प्राकृतिक सुगंध वाले कंडीशनर का चयन करें। इससे न केवल आपके बाल महकेंगे बल्कि आपकी त्वचा भी सुरक्षित रहेगी और कोई परेशानी नहीं होगी।

सही मात्रा में उपयोग करें

कंडीशनर का उपयोग करते समय सही मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा कंडीशनर लगाने से बाल चिपचिपे हो सकते हैं, इसलिए मात्रा का सही उपयोग करें। आमतौर पर बालों की लंबाई के हिसाब से एक-दो नट या छोटी चम्मच पर्याप्त होती है।

इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने बालों के लिए सही कंडीशनर चुन सकते हैं, जो उन्हें मजबूती देगा और उन्हें स्वस्थ बनाए रखेगा।



मेडिकल चेकअप के लिए तैयार होते समय अपनाएं ये पांच तरीके, होगा फायदा

मेडिकल चेकअप से हमारा मतलब है जब डॉक्टर हमें चेकअप के लिए बुलाएं तो उससे पहले हमें क्या-क्या करना चाहिए ताकि हमारा चेकअप सही से हो सके। इसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है। हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने मेडिकल चेकअप के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं और डॉक्टर से मिलने पर आपकी समस्या का सही समाधान मिल सके।

मिलने का समय पहले से तय करें

मेडिकल चेकअप के लिए सबसे पहले आपको मिलने का समय पहले से तय करना चाहिए। इससे आपको समय पर डॉक्टर से मिलने का मौका मिलेगा और आपकी समस्या का सही समाधान मिल सकेगा। समय तय करने से आप अपनी समस्या के बारे में पहले से ही सोच सकते हैं और डॉक्टर से पूछने के लिए जरूरी सवाल तैयार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके चेकअप को अधिक असरदार और सुविधाजनक बनाती है।

जरूरी कागजात साथ रखें

चेकअप के दौरान डॉक्टर को आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी जानना जरूरी होता है इसलिए सभी जरूरी कागजात जैसे कि पिछले रिपोर्ट्स, दवाइयों की सूची और अन्य जानकारी साथ लेकर जाएं। इससे डॉक्टर को आपकी स्थिति समझने में मदद मिलेगी और वह आपको सही सलाह दे सकेगा। अगर आपके पास कोई खास बीमारी या समस्या है तो उसके बारे में भी कागजात तैयार रखें। इससे डॉक्टर को आपकी स्थिति का पूरा पता चलेगा और वह आपको बेहतर इलाज दे सकेगा।

समय पर पहुंचें

चेकअप के समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि आपको इंतजार न करना पड़े और आपका समय भी बर्बाद न हो। अगर आप समय पर पहुंचेंगे तो डॉक्टर भी आपकी समस्या को ध्यान से सुन पाएंगे और आपको बेहतर सलाह दे सकेंगे।

समय पर पहुंचने से न केवल आपका समय बचेगा बल्कि डॉक्टर को भी आराम से आपकी समस्या का पता लगाने का मौका मिलेगा। इससे आपका चेकअप अधिक असरदार और सुविधाजनक बनेगा।

खाली पेट रहें (अगर जरूरी हो)

कुछ जांच के लिए आपको खाली पेट रहना पड़ सकता है जैसे कि खून की जांच या अल्ट्रासाउंड आदि।

इसके लिए पहले से ही डॉक्टर से पूछ लें ताकि आपको कोई परेशानी न हो।

अगर डॉक्टर ने कहा है कि खाली पेट रहना जरूरी है तो उसके अनुसार ही तैयार रहें और समय पर सभी निर्देशों का पालन करें। इससे आपका चेकअप सही तरीके से होगा और डॉक्टर को आपकी स्थिति का सही पता चलेगा।

सवाल तैयार रखें

चेकअप के दौरान आपको कई सवाल पूछने पड़ सकते हैं जैसे कि आपकी समस्या कब से है, क्या आपने पहले कोई इलाज कराया था, क्या दवाइयां ले रहे थे आदि। इन सवालों की तैयारी पहले ही कर लें ताकि डॉक्टर को आपकी स्थिति समझने में आसानी हो।

इसके अलावा अगर आपके मन में कोई अन्य सवाल हो तो उन्हें भी तैयार रखें ताकि आपके चेकअप का पूरा फायदा मिल सके।

स्काउटओपी ने लव गिल के साथ अपने रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, भावुक होकर बताई पूरी कहानी

बिग बॉस 20 के आगामी एपिसोड के प्रोमो में स्काउटओपी सह-प्रतियोगी लव गिल के साथ अपनी दोस्ती को लेकर भावुक होते नजर आएंगे। घर की लाइटें बंद होने के बाद गुल्लू से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि लव हमेशा उनका ख्याल रखती थीं। वह समय पर खाना खाने से लेकर उनके कपड़े धोने तक का ध्यान रखती थीं। स्काउट ने इस रिश्ते में लगाए गए अपने समय और भावनात्मक जुड़ाव पर भी बात की।



स्काउट ने बातचीत के दौरान कहा, एक इंसान के पीछे मैंने कितना समय खराब किया है। उन्होंने आगे बताया कि जब वे दोस्त थे, तब लव किस तरह उनका ख्याल रखती थीं। उन्होंने कहा, वह यह पक्का करती थीं कि मैं समय पर खाना खा रहा हूं।

स्काउट ने आगे बताया कि एक बार उन्होंने लव से रोज अपने बालों में तेल लगाने के लिए कहा था और उन्होंने सच में ऐसा किया भी। स्काउट और लव साथ में कैसे समय बिताते थे, इस बारे में बताते हुए स्काउट ने कहा कि वे रोज एक ही बिस्तर पर बैठकर बातें करते थे।

उन्होंने आगे कहा, वह बिस्तर एक हब बन गया था। लव 30-30 सेकंड तक बस मुझे देखती ही रहती थी।

खुद की तुलना खाने का लालच देकर फुसलाए जा रहे चूहे से करते हुए स्काउट ने कहा, जैसे कोई चूहा भाग रहा हो और आप उसे खाना देकर इधर-उधर बुला रहे हो।

स्काउट ने इसके बाद खुद से ही सवाल किया कि आखिर उन्होंने लव को इतनी अहमियत क्यों दी थी।

स्काउट ने उस घटना को भी दोहराया जिसमें उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था।

अपनी मन:स्थिति को याद करते हुए उन्होंने कहा, मतलब मेरे अंदर गुस्सा कितना ज्यादा होगा कि मैंने अपने बाल काट दूं, जिससे गुस्सा थम जाए। उन्होंने बात खत्म करते हुए बोला, जिंदगी में कितना ट्रॉमा दे दिया।

खास-खबर

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए 18 शिक्षकों को मिले नियुक्ति आदेश

खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के छह स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए खुली काउंसलिंग हुई। इसमें 18 अभ्यर्थियों ने अपनी पसंद के विद्यालय चुने। कलेक्टर एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष इन्द्रजीत सिंह चंद्रवाल के अनुमोदन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी उपेंद्र कुमार देवांगन ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश प्रदान किए। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के छह विद्यालयों में शिक्षकों के 25 रिक्त पदों के लिए राज्य कार्यालय से 23 अभ्यर्थियों की चयन सूची प्राप्त हुई थी। 25 नवंबर को दस्तावेज सत्यापन के दौरान हिंदी माध्यम से होने के कारण दो अभ्यर्थी अपात्र पाए गए। शेष 21 पात्र अभ्यर्थियों में से 18 काउंसलिंग में शामिल हुए और तीन अनुपस्थित रहे।

राष्ट्रीय मखाना सेमिनार में बालोद के 47 किसानों ने लिया प्रशिक्षण

बालोद। किसानों की आय बढ़ाने और खेती-किसानी में नई संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिले के 47 किसानों ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार में सहभागिता की। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार कृषि विज्ञान केंद्र बालोद द्वारा जिले के विभिन्न गांवों के किसानों को इस राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम में शामिल कराया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में 26 एवं 27 नवंबर को आयोजित इस सेमिनार में किसानों को मखाना की खेती की आधुनिक तकनीकों, उत्पादन की संभावनाओं और प्रसंस्करण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।

निविदा मंजूरी के बाद चयनित एजेंसी को 15 दिनों में कार्यादेश जारी करने के निर्देश

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज पांचों परिक्षेत्रों, सेतु बंध, विद्युत एवं यांत्रिकी, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख अभियंता कार्यालय के सभी मुख्य अभियंताओं की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में निर्माणाधीन भवनों, सड़कों एवं पुलों के साथ ही नए कार्यों की निविदा प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ऐसे कार्यों जिनकी निविदा स्वीकृत हो गई हैं, उनके कार्यादेश चयनित ठेकेदारों एवं एजेंसियों को 15 दिनों के भीतर जारी करने के निर्देश दिए, जिससे कि वर्किंग सीजन का पूरा उपयोग करते हुए कार्यों में अच्छी प्रगति लाई जा सके। उन्होंने सभी मुख्य अभियंताओं को हर सप्ताह कम से कम दो दिन फील्ड में जाकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और गति पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।

बच्चों के बचपन की रक्षा में समाज की भागीदारी जरूरी : लक्ष्मी राजवाड़े

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुप्रथा नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सपनों पर असर डालने वाली गंभीर चुनौती है। बच्चों को पढ़ने, आगे बढ़ने और अपनी राह चुनने का अवसर देना परिवार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय 'बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़-जन-संवाद' कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने 'बाल विवाह मुक्ति रथ' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और 100 दिवसीय जन-जागरण अभियान का शुभारंभ किया।

बाल विवाह मुक्ति रथ रवाना : 100 दिवसीय जन-जागरण अभियान शुरू





बच्चों के अधिकारों पर हुआ संवाद

अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह निषेध दिवस और 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बाल विवाह की रोकथाम, बच्चों के अधिकारों और इस प्रयास में समाज की भूमिका पर चर्चा हुई। बच्चों के साथ विशेष जन-संवाद में बाल प्रहरियों ने बाल विवाह रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों और अपने अनुभवों को साझा किया। बाल विवाह रोकने में साहसिक भूमिका निभाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने उपस्थित लोगों को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण की सामूहिक शपथ भी दिलाई।

मंत्री राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 27 नवंबर 2024 को शुरू हुआ 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश को बाल विवाह से मुक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 10 मार्च 2024 को 'बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान' शुरू किया गया था। गांव-गांव में जागरूकता गतिविधियों के साथ पंचायतों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्थानीय प्रशासन और समुदाय के सहयोग से बाल विवाह रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि बालोद जिले की 436 ग्राम पंचायतों और 9 नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त होने का प्रमाणपत्र दिया गया है। सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतें भी बाल विवाह मुक्त घोषित की गई हैं। सूचना मिलने पर प्रदेश में 800 से अधिक बाल विवाह रुकवाए गए हैं। बच्चों की सहायता और सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, नोनी सुरक्षा योजना और महतारी वंदन योजना जैसी पहल बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर दे रही हैं। बाल विवाह की सूचना मिलने पर उसे गंभीरता से लेना और रोकथाम में सहयोग करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वर्ष 2030 तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य सामूहिक संकल्प और लगातार प्रयासों से हासिल किया जा सकता है।

अतिथियों ने साझा किए विचार

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार ने छत्तीसगढ़ में बाल विवाह की स्थिति और रोकथाम के प्रयासों की जानकारी दी। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकथाम के कार्यों पर ओम प्रकाश पाल ने विचार रखे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक धनंजय टिंगल ने भी संबोधित किया। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बाल अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह उन्मूलन में आयोग की भूमिका पर प्रकाश डाला। विधायक पुरंदर मिश्रा और उद्धेश्वरी पैकरा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने आभार व्यक्त किया।

हरियाली से संवर रहा खिसोरा का भविष्य, बंजर भूमि पर विकसित हो रहा हरित उद्यान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक पहल की जा रही है। धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड की ग्राम पंचायत खिसोरा में सामुदायिक भागीदारी से बंजर भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। कभी वीरान नजर आने वाली चारागाह भूमि अब हरियाली की नई तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। वीबी-जी राम जी के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में सात एकड़ चारागाह भूमि पर 9.57 लाख रुपये की लागत से विभिन्न प्रजातियों के एक हजार पौधे लगाए गए हैं। इनमें से वर्तमान में 880 पौधे जीवित हैं। खिसोरा में पर्यावरण संरक्षण की इस पहल के तहत आम, जामुन, करौंदा, गुलमोहर, आंवला, पीपल और बरगद सहित विभिन्न फ्लदार, औषधीय एवं छायादार प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं।

आने वाले वर्षों में ये पौधे ग्रामीणों को फ्ल, पोषण और छाया उपलब्ध कराने के साथ जैव विविधता के संरक्षण तथा स्थानीय पर्यावरण को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। वृक्षारोपण से मिट्टी के कटाव को रोकने, वर्षा जल के संचयन और भूमि में नमी बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। इस पहल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वृक्षारोपण के साथ पौधों के दीर्घकालीन संरक्षण की व्यवस्था है।

कूच बिहार ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ की मजबूत पकड़, बड़ौदा पहली पारी में 144 रनों पर सिमटा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बीसीसीआई द्वारा मेंस अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी 2026 का आयोजन 26 नवंबर 2026 से किया जा रहा है। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम का पहला चार दिवसीय मुकाबला 26 से 29 नवंबर 2026 तक सेक्टर-10 मैदान, भिलाई में बड़ौदा अंडर-19 टीम के विरुद्ध खेला जा रहा है।

दूसरे दिन बड़ौदा अंडर-19 ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 98.1 ओवरों में सभी 10 विकेट खोकर 314 रन बनाए। छत्तीसगढ़ की ओर से अमितेश मिश्रा ने 88 रनों की शानदार पारी खेली। आदित्य यादव ने 75 रन बनाकर टीम के स्कोर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके अतिरिक्त अर्शवीर सिंह भाटिया ने 39 रन तथा वेदांश खेडिया ने 28 रन बनाए। बड़ौदा की ओर से अनिकेत जोशी ने 4 विकेट प्राप्त किए, जबकि विवान, जैनम पटेल और गौरव चौधरी ने 2-2 विकेट हासिल किए। छत्तीसगढ़ के 314 रनों के जवाब में बड़ौदा की टीम अपनी पहली पारी में 62 ओवरों में सभी 10 विकेट खोकर केवल 144 रन ही बना सकी। बड़ौदा की ओर से पृथ्वी ओडेड्रा ने 46 रन, सन्नी कलारिया ने 31 रन तथा जीत पटेल ने 25 रनों का योगदान दिया।





छत्तीसगढ़ की ओर से अर्शवीर सिंह भाटिया ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके। धनंजय नायक ने भी प्रभावी गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट प्राप्त किए। पहली पारी में 170 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद छत्तीसगढ़ ने अपनी दूसरी पारी में दिन की समाप्ति तक 17 ओवरों में 2 विकेट खोकर 38 रन बना लिए हैं। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक छत्तीसगढ़ ने कुल 208 रनों की बढ़त बना ली है और मुकाबले में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

छत्तीसगढ़ अंडर-16 ने कर्नाटक के खिलाफ हासिल की पहली पारी की बढ़त, मुकाबला ड्रॉ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बीसीसीआई द्वारा मेंस अंडर-16 विजय मर्चेंट मल्टी डे ट्रॉफी 2026 का आयोजन 14 नवंबर 2026 से किया जा रहा है। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम का तीसरा तीन दिवसीय मुकाबला 25 से 27 नवंबर 2026 तक लखनऊ में कर्नाटक अंडर-16 टीम के विरुद्ध खेला गया। मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ ने पहली पारी में बढ़त हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया।

तीसरे दिन कर्नाटक अंडर-16 ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ ने अपनी पहली पारी में 119.4 ओवरों में सभी 10 विकेट खोकर 421 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। छत्तीसगढ़ की ओर से आर्यन अग्रवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 123 रनों की



शतकीय पारी खेली। आदित्य बैदवाल शतक से महज एक रन दूर रह गए और 99 रन बनाकर आउट हुए। उज्ज्वल मरकाम ने 75 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान अशुमन ठाकुर ने 33 रनों का योगदान दिया। कर्नाटक की ओर से भुवन गौड़ा और आयुष ने 4-4 विकेट प्राप्त किए। इसके जवाब में कर्नाटक ने भी कड़ा संघर्ष करते हुए अपनी पहली पारी में 143.2 ओवरों में सभी 10 विकेट खोकर 408 रन बनाए। कर्नाटक की ओर से रोहित रेड्डी ने शानदार 130 रन बनाए। प्रीतम ने 86 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली, जबकि विआन जोशी ने 67 और शिवराज ने 30 रन बनाए। छत्तीसगढ़ की ओर से आदित्य बैदवाल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किए। चंद्रप्रकाश साहू ने भी 2 विकेट प्राप्त किए। इस प्रकार मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। छत्तीसगढ़ ने पहली पारी में 13 रनों की बढ़त हासिल कर कर्नाटक के खिलाफ अपना दमदार प्रदर्शन दर्ज कराया। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में खिलाड़ियों के शानदार योगदान से छत्तीसगढ़ की टीम ने मुकाबले में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

श्रम अधिकारियों को सायबर अपराध से सुरक्षा के दिए गए टिप्स

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। लगातार बढ़ रहे तकनीकी एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के साइबर सिक्योरिटी डिविजन के अधिकारियों द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया।

इस दौरान वर्तमान परिदृश्य में सायबर धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और ठगी के बढ़ते अपराधों से बचाव व सुरक्षा के ठोस उपायों की जानकारी श्रम, उद्योग एवं वाणिज्यिक कर मंत्री लखन लाल देवांगन तथा श्रम सचिव, श्रमायुक्त सह मुख्य कारखाना निरीक्षक हिमशिखर गुप्ता की मौजूदगी में पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से



दी गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, यूपीआई फ्रॉड, फिशिंग, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, साइबर बुलिंग, सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन निवेश एवं टास्क फ्रॉड तथा डिजिटल अरेस्ट जैसे गम्भीर साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि साइबर अपराधी किस प्रकार फर्जी कॉल, मैसेज, लिंक एवं एपीके फाइल के माध्यम से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जाने वाली ठगी से सतर्क रहने और किसी भी परिस्थिति में **OTP, PIN** या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने की सलाह इस दौरान दी गई। प्रशिक्षण में साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

सिरपुर महोत्सव 2027 में सजेगा इतिहास अध्यात्म और संस्कृति का अनुपम संगम

20 से 22 फरवरी तक ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में होगा तीन दिवसीय महोत्सव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक एवं सांस्कृतिक विरासत को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में महासमुंद जिले के ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक नगरी सिरपुर में 20 से 22 फरवरी 2027 तक तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 'संगीति' की अवधारणा पर आधारित इस महोत्सव में इतिहास, अध्यात्म, कला, संस्कृति एवं पर्यटन का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। महोत्सव को भव्य, आकर्षक एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा समन्वित कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

सिरपुर महोत्सव की तैयारियों के संबंध में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में अंतरविभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी धम्मशील गणवीर ने महोत्सव के आयोजन एवं क्रियान्वयन की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की। सचिव ने विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक स्थानीय एवं क्षेत्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। इसके पश्चात शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव के प्रत्येक दिवस की विषयवस्तु के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके लिए उपयुक्त स्थलों का चयन एवं निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटकों के लिए तंबू नगरी, गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी, नौका विहार एवं साहसिक खेलों जैसी गतिविधियों के संबंध में भी कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को संबंधित पर्यटन सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय स्थापित करने तथा आवश्यक अनुमतियां एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।



सुरंग टीला में जीवंत होगा सिरपुर का गौरवशाली इतिहास

सिरपुर महोत्सव का प्रमुख आकर्षण ऐतिहासिक सुरंग टीला में प्रारंभ होने वाला प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम होगा। इसके माध्यम से सिरपुर के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध पुरातात्त्विक विरासत तथा प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग की सिरपुर यात्रा से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। महोत्सव के दौरान इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा तथा महोत्सव के बाद भी इसका संचालन जारी रहेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण एवं राज्य पुरातत्त्व संचालनालय को समन्वय स्थापित कर आवश्यक तैयारियां समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्थानीय लोक कलाकारों को मिलेगा विशेष मंच

सिरपुर महोत्सव में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति एवं पारंपरिक नृत्य विधाओं को विशेष स्थान दिया जाएगा। महोत्सव में 34 ग्रामों के पारंपरिक नृत्य दलों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों के लिए अलग मंच एवं आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। शास्त्रीय एवं लोक कलाओं की उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के चयन के लिए समिति गठित की जाएगी। कलाकारों का चयन सांस्कृतिक महत्व, प्रस्तुति की गुणवत्ता, विविधता एवं महोत्सव की विषयवस्तु के अनुरूप किया जाएगा।

समाज को दिशा देते हैं पत्रकार : साव

बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पत्रकार जनसमस्याओं की आवाज बनकर समाज को दिशा देते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने और उनके समाधान का मार्ग प्रशस्त करने में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने समाचार के प्रकाशन एवं प्रसारण से पहले तथ्यों की पुष्टि करने और समाज पर उसके संभावित प्रभाव का ध्यान रखने का आह्वान किया। श्री साव बिलासपुर के स्व. लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अवस्थी और प्रदेश महासचिव विश्व दीपक राय उपस्थित थे।

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

ढाबे के पास चिट्टा बेच रहे दो युवक गिरफ्तार, 4.66 लाख का माल जब्त

भिलाई। जामुल थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान के पास नशे का कारोबार कर रहे दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों कुरूद रंगला पंजाब ढाबा के पास बस स्टैंड में हेरोइन (चिट्टा) बेच रहे थे। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी में उनके कब्जे से 24.45 ग्राम हेरोइन, तीन मोबाइल फोन और बिक्री के 3200 रुपए नकद मिले। जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 4 लाख 66 हजार 800 रुपए बताई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों ओंकार सिंह (23), खुर्सीपार और लुकेश कुमार सिंह (29), निवासी कैंप-1 भिलाई के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर शुक्रवार को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

मांड नदी में रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई, 21 वाहन जब्त

रायगढ़। मांड नदी में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर भास्कर की खबर के बाद खनिज विभाग ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। विभाग के उड़नदस्ता दल ने सुबह 6 बजे लेबड़ा-देवरी-रानीगुड़ा क्षेत्र में दबिश देकर 21 वाहनों को जब्त किया। इनमें एक चैन माउंटेन मशीन, 4 जेसीबी, एक ट्रैक्टर लोडर और 15 ट्रैक्टर शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान चैन माउंटेन मशीन को मौके पर ही सील कर दिया गया। वहीं 5 ट्रैक्टर खरसिया थाने की अभिरक्षा में रखे गए हैं। जिले में रेत घाटों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन घाटों का विधिवत संचालन शुरू होने से पहले ही मांड नदी में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा था। भास्कर ने लेबड़ा घाट की पड़ताल में पाया था कि ट्रैक्टरों के जरिए रेत निकाल हाइवा में लोड की जा रही है। पहले टीम पहुंचने तक तस्कर भाग जाते थे, इसलिए शुक्रवार सुबह 5 बजे कई रास्तों की घेराबंदी कर दबिश दी गई। मौके से चैन माउंटेन मशीन, ट्रैक्टर और लोडर वाहन मिले।

सोलर पैनल लगाने के नाम पर 34 लाख की ठगी मुंबई जेल में बंद आरोपी को दुर्ग लाई पुलिस

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सोलर पैनल बाजार दर से कम कीमत पर उपलब्ध कराने एवं ग्राहकों के यहां इंस्टॉलेशन कराने का झांसा देकर 34 लाख की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने मुंबई से आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा एवं कोटक महिंद्रा बैंक के खातों से IMPS एवं RTGS के माध्यम से आरोपियों से संबंधित कंपनी के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की गई थी। शिकायत पर थाना सुपेला, चौकी स्मृतिनगर में धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस ने विवेक मिश्रा को मुंबई से ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग लाया गया है। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना एवं पूछताछ जारी है।

प्रार्थी नवीन कुमार द्वारा 5 सितंबर 2026 को चौकी स्मृतिनगर में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि दिनांक 24.06.2026 को मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क करने वाले स्नेहा एवं कंपनी मैनेजर कमलेश पाटिल द्वारा स्वयं को सनरुट एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित बताकर प्रार्थी की फर्म को बाजार दर से कम कीमत पर सोलर पैनल उपलब्ध कराने तथा ग्राहकों के यहां इंस्टॉलेशन कराने का प्रस्ताव दिया गया।

आरोपियों द्वारा विश्वास में लेकर प्रार्थी से कंपनी के नाम पर राशि जमा कराई गई। इस पर प्रार्थी द्वारा अपने बैंक ऑफ बड़ौदा, नंदनी रोड भिलाई एवं कोटक महिंद्रा बैंक, सुपेला स्थित खातों से IMPS एवं RTGS के माध्यम से कुल 34,00,000/- कंपनी के ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक, मुंबई स्थित खाते में हस्तांतरित किए गए। बाद में धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत पर थाना सुपेला, चौकी स्मृतिनगर में अपराध क्रमांक 1306/2026, धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान साइबर सेल एवं संबंधित बैंकों से संदिग्ध मोबाइल नंबरों तथा बैंक खातों की जानकारी प्राप्त की गई। प्रार्थी के कथन एवं



विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पर आयुष उपाध्याय एवं विवेक मिश्रा के नाम सामने आए। दोनों आरोपी थाना बांगुर नगर, मुंबई के अपराध क्रमांक 880/2026, धारा 316(2), 318(4), 3(5) बीएनएस के प्रकरण में पूर्व से गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में सेंट्रल जेल मुंबई में निरुद्ध थे। चौकी स्मृतिनगर पुलिस टीम द्वारा स्थानीय पुलिस एवं जेल प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय दुर्ग से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया गया। इसके पश्चात वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर दोनों आरोपियों को मुंबई से एक को ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग लाया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरांत पुलिस रिमांड प्राप्त कर प्रकरण में अग्रिम पूछताछ एवं विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त कार्यवाही में चौकी स्मृतिनगर के उप निरीक्षक दीपक चौहान, प्रधान आरक्षक क्रमांक 134 जितेन्द्र कुशवाह एवं आरक्षक क्रमांक 1185 राजकुमार चन्द्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम द्वारा अन्य राज्य में जाकर स्थानीय पुलिस एवं जेल प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर आरोपियों को दुर्ग लाने की कार्यवाही की गई। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील करती है कि किसी भी कंपनी या व्यक्ति से ऑनलाइन व्यापारिक लेन-देन करने से पूर्व उसकी वैधता, पंजीयन, कार्यालय एवं बैंक खाते की प्रमाणिकता की जांच अवश्य करें। बाजार दर से असामान्य रूप से कम कीमत पर सामान उपलब्ध कराने के प्रस्तावों के प्रति सतर्क रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति या कंपनी के खाते में बिना समुचित सत्यापन के बड़ी धनराशि हस्तांतरित न करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं।

फर्जी दस्तावेज बनाकर हड़पी पैतृक जमीन, पति-पत्नी समेत 3 गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। दुर्ग जिले के ग्राम डुण्डेरा में पैतृक कृषि भूमि को फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने नाम कराने के आरोप में उतई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें शिवकुमार साहू, उसकी पत्नी सीमा साहू और कौशल कुमार साहू शामिल हैं।

पन्नालाल साहू ने 10 नवंबर 2026 को दुर्ग एसएसपी के सामने शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता बोधीराम साहू भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। ग्राम डुण्डेरा में उनके नाम छह खसरों की कृषि भूमि दर्ज थी।

परिवार का कहना है कि बोधीराम साहू ने शिवकुमार साहू या उसकी पत्नी के साथ जमीन बेचने का कोई सौदा नहीं किया था। इसके बावजूद जमीन उनके नाम से दूसरे के नाम करा दी गई।



शिकायत के मुताबिक, 24 सितंबर 2022 को 60 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बोधीराम साहू के नाम से इकरारनामा तैयार किया गया। इसमें कौशल साहू और सुमनलाल साहू को गवाह बनाया गया था। इसके बाद 18 नवंबर 2022 को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बिक्री नामा तैयार किया गया। आरोप है कि शिवकुमार साहू ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दस्तावेज तैयार कराए और जमीन पत्नी सीमा साहू के नाम कराने की प्रक्रिया पूरी की।

छह खसरों की जमीन को लेकर विवाद

शिकायत के अनुसार, बोधीराम साहू के नाम ग्राम डुण्डेरा में खसरा नंबर 279/1, 1079, 1080/2, 1081, 1352 और 1412/1 की कृषि भूमि दर्ज थी। परिवार का दावा है कि वे लंबे समय से इस जमीन पर काबिज थे। पन्नालाल और उनके भाई अरुण कुमार साहू दोनों शासकीय सेवा में शिक्षक हैं।

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

जांच के बाद उतई थाने में अपराध क्रमांक 568/2026 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 और 34 भादवि में केस दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने शिवकुमार साहू, सीमा साहू और कौशल कुमार साहू को गिरफ्तार किया।

शिकायत में पांच नाम, तीन की गिरफ्तारी

पन्नालाल साहू ने अपनी शिकायत में शिवकुमार साहू, सीमा साहू, रोहित साहू, कौशल साहू और सुमनलाल साहू के नाम दिए थे। हालांकि, पुलिस की 27 नवंबर की प्रेस विज्ञप्ति में केवल शिवकुमार, सीमा और कौशल की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। बाकी दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की गई है।

जगदलपुर में 12.10 लाख की नशीली दवा पकड़ाई, दो आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

जगदलपुर। बस्तर में नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक, 26 नवंबर को सूचना मिली थी कि रानी घाट के पास एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो में दो युवक नशीली कैप्सूल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना पर एसपी शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपियों की



पहचान मनीष प्रकाश सावल (33), निवासी नयापारा आड़ावाल और सुमित पांडेय (29), निवासी पनारापारा विजय वार्ड, जगदलपुर के रूप में हुई है। इनमें कुल 216 कैप्सूल थीं। पुलिस ने कैप्सूल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर विशेष एनडीपीएस न्यायालय, जगदलपुर में पेश किया गया।

हिमाचल के होटल से छत्तीसगढ़ में ड्रग्स की सप्लाई : नाइजीरियन से खरीदते थे, रायपुर में 3 आरोपियों को 20-20 साल की सजा, 6 बरी

रायपुर। रायपुर के चर्चित ड्रग्स तस्करी मामले में एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट ने 9 आरोपियों में से 3 को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में आर्यन ठाकरे, नाइजीरियाई नागरिक इनोसेंट और शुभम सोनी शामिल हैं। दरअसल, टिकरापारा थाने में साल 2024 में दर्ज मामले में आरोपी शुभम सोनी के मेमोरेंडम बयान के आधार पर 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें आर्यन ठाकरे, नाइजीरियाई नागरिक इनोसेंट, ओयनका स्टीफेन, अमनदीप छाबड़ा, अभिषेक, लोकेश यादव और अशोक साहू के नाम शामिल थे। इस तरह मामले में कुल 9 आरोपी थे।

पुलिस की जांच में रायपुर से हिमाचल प्रदेश के कसोल और दिल्ली तक ड्रग्स सप्लाई का नेटवर्क सामने आया था। आरोपियों के पास से चरस, एमडीएमए और कोकीन बरामद की गई थी। पुलिस के मुताबिक, 23 सितंबर 2024 को मुखबिर की सूचना पर टिकरापारा पुलिस ने कमल विहार सेक्टर-4 चौक स्थित ऑक्सीजोन के पास कार्रवाई की थी।



इस दौरान शुभम सोनी के पास से 31.88 ग्राम चरस, 98 एमडीएमए टैबलेट, एक लोहे की पिस्टल और खाली मैगजीन बरामद की गई थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, खाली कैप्सूल, एक लाख रुपए कैश और दो स्मार्टफोन भी मिले थे। अभिषेक साहू उर्फ चीनी के मेमोरेंडम बयान के मुताबिक, शुभम सोनी उसका दोस्त था और आयुष अग्रवाल के साथ एमडीएमए और चरस बेचने का काम करता था। शुभम उसे ड्रग्स मंगाने के लिए पैसे देता था। अभिषेक यह रकम अमनदीप सिंह छाबड़ा के बताए बैंक खाते में जमा करवाता था। अभिषेक के मुताबिक, अमनदीप वॉट्सऐप और स्नैपचैट पर ड्रग्स की तस्वीरें भेजता था। इसके बाद आर्यन ठाकरे सुनसान जगह पर माल लेकर पहुंचता था। अभिषेक उससे ड्रग्स लेकर शुभम सोनी को देता था। इस काम के बदले उसे हर बार 25 हजार रुपए कमीशन मिलता था।

अभिषेक ने अपने बयान में बताया कि, शुभम से फोन कॉल रिकॉर्ड होने और पुलिस के पकड़ने के डर से वह स्नैपचैट पर बातचीत करता था। उसने करीब एक सप्ताह पहले शुभम से 3 लाख रुपए कैश लिए थे। इसके बाद अमनदीप से वॉट्सऐप कॉल पर बातकर नाजरे आलम नाम के व्यक्ति के कोटक महिंद्रा बैंक खाते में यह रकम जमा कराई थी। अभिषेक के मुताबिक, अमनदीप के भेजे गए मैसेज की चैटिंग भी उसके मोबाइल में मौजूद थी।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में इंजीनियर गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर में 16 साल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और उसका गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। मामले में डीडी नगर थाना पुलिस ने राजस्थान के दौसा के हिमांशु जाटव को गिरफ्तार किया है। आरोपी एनआईटी से पढ़ाई पूरी कर चुका है। उस पर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने और उसके गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर गर्भपात कराने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, हिमांशु एनआईटी में पढ़ाई के दौरान रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहता था। इसी दौरान उसकी पहचान छात्रा से हुई थी। आरोप है कि इसी



दौरान उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।

गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर दिल्ली से आया रायपुर

पुलिस के अनुसार, पढ़ाई पूरी करने के बाद आरोपी रायपुर छोड़कर दिल्ली चला गया था। कुछ समय बाद छात्रा ने उसे फोन कर गर्भवती होने की जानकारी दी। इसके बाद हिमांशु दिल्ली से रायपुर पहुंचा। आरोप है कि यहां उसने छात्रा का गर्भपात करा दिया। इस पूरे मामले की जानकारी छात्रा के परिजनों को मिलने पर उन्होंने डीडी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि छात्रा का गर्भपात कहां और किसकी मदद से कराया गया। इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

20 कबाड़ियों के ठिकानों पर पुलिस की रेड

800 किलो कबाड़ जब्त, 10 कबाड़ियों के पास नहीं मिले वैध दस्तावेज



श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर में अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ उत्तर जोन पुलिस ने कार्रवाई की है। उरला और खमतराई इलाके में पुलिस ने एक साथ 20 कबाड़ियों के ठिकानों पर जांच और छापेमारी की।

इस दौरान 10 कबाड़ियों के यहां से करीब 8 टन कबाड़ जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक, जब्त माल के संबंध में वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं।

यह कार्रवाई डीसीपी उत्तर जोन दीपमाला कश्यप, एडीसीपी आदित्य पांडेय और एसीपी पूर्णिमा लामा के निर्देश पर की गई। पुलिस टीमों ने कबाड़ियों के ठिकानों पर पहुंचकर वहां रखे स्क्रैप और खरीदी-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच की।

पुलिस के मुताबिक, उरला थाना क्षेत्र में 8 कबाड़ियों के ठिकानों की जांच की गई। इनमें से 6 के यहां से कबाड़ जब्त किया गया। वहीं, खमतराई थाना क्षेत्र में 12 कबाड़ियों के ठिकानों पर जांच की गई, जिनमें से 4 के यहां से माल मिला। इस तरह कुल 10 कबाड़ियों से करीब 8 टन कबाड़ जब्त किया गया।

पुलिस अब कबाड़ कारोबारियों से स्क्रैप की खरीदी-बिक्री से जुड़े दस्तावेज, रजिस्टर और लाइसेंस की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि जब्त कबाड़ कहां से खरीदा गया था। पुलिस का कहना है कि जांच में चोरी का माल खरीदने या अवैध कारोबार में शामिल होने की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत की गई है। उत्तर जोन पुलिस ने अवैध कारोबार और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है।

NAME CHANGE

It is informed to the General Public that I, PUSHPENDRA KUMAR CHATURVEDI S/o JAGAT RAJ CHATURVEDI, Resident of H.No. 191, Bangali Mohalla, Sangam Chowk, New Khursipar, Bhilai. Distt-Durg (C.G.) 490011 have changed my old name to new name i.e. PUSHPENDRA CHATURVEDI so that I should be recognized by my new name that is PUSHPENDRA CHATURVEDI S/o JAGAT RAJ CHATURVEDI in all Government and other documents.

PUSHPENDRA KUMAR CHATURVEDI
H.No. 191, Bangali Mohalla, Sangam Chowk, New Khursipar, Bhilai. Distt-Durg (C.G.) 490011

//कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला-दुर्ग (छ.ग.)//

।। तृतीय निविदा सूचना।।

क्रमांक/आब./निविदा/2026/ दुर्ग, दिनांक :

जिला दुर्ग अंतर्गत शासन द्वारा संचालित प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान भिलाई के स्थल परिवर्तन हेतु भवन/दुकान/परिसर को किराये पर लेने बाबत् कानूनी मालिकों से मुहर बंद निविदाएं (तकनीकी शर्तों से संबंधित दस्तावेज एवं रेट ऑफर पृथक-पृथक बंद लिफाफों में) आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तों तथा निविदा संबंधी अन्य जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-दुर्ग (उप महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, दुर्ग) के कक्ष क्रमांक 44 से अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

क.	मदिरा दुकान का नाम	प्रस्तावित स्थल जहां दुकान स्थापित/स्थानांतरण होना है	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं प्राप्ति
1	प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान भिलाई	नगर पालिक निगम भिलाई के सीमा क्षेत्र में मदिरा दुकान के वर्तमान स्थल से 500 मीटर के परिधि में आपत्ति रहित स्थल।	डिमांड ड्राफ्ट रू. 1180/- (रू. 1000 एवं जीएसटी रू. 180) उप महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड जिला-दुर्ग(छ.ग.) के पक्ष में देय, का भुगतान कर जारीकर्ता कार्यालय से कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकाता है।

निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि 07.12.2026 समय अपरान्ह 12:00 बजे तक।
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 07.12.2026 समय दोपहर 02:00 बजे तक।
निविदा खोलने की तिथि 07.12.2026 समय सायं 04:00 बजे।

(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त आबकारी,
हेतु कलेक्टर
जिला-दुर्ग(छ.ग.)

जी-262704778/3

कार्यालय कलेक्टर दुर्ग (छ0ग0) एवं पदेन विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

--:: सार्वजनिक सूचना ::--

क्रमांक/2326/भू-अर्जन/आ0क्र0नि0-16 दिनांक 26/10/2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग संभाग दुर्ग को निकुम-विनायकपुर-अण्डा मार्ग निर्माण (लंबाई 13.60 कि0मी0) हेतु ग्राम-निकुम प0ह0नं0 29 राजस्व निरीक्षण मंडल अण्डा तहसील व जिला दुर्ग (छ0ग0) स्थित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अत: राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की आपसी सहमति से क्रय नीति-2016 के प्रावधानो के तहत अनुसूची में वर्णित भूमि को कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग संभाग दुर्ग (छत्तीसगढ़) के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

(क्रय की जाने वाली भूमि व कृषको के विवरण)

स0 क्रमॉक	भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम	क्रय की जाने वाली भूमि हेक्टर में एवं परिसंपत्तिं का विवरण	
		खसरा नम्बर	प्रभावित रकबा हे0 एवं परिसम्पति
1	2	3	4
01	1. हेमन्त कुमार पिता नीलूराम 2. नीलम अमृत पति इन्द्रकुमार 3. शुभम अमृत (ना0बा0) पिता इन्द्रकुमार 4. माही अमृत (ना0बा0) पिता इन्द्रकुमार 5. दिनेश्वर प्रसाद पिता नीलूराम 6. शांति बाई पिता नीलूराम	940	0.0025
02	डालेश्वर पिता चेतन लाल	941	0.0018
योग	कुल योग 02 कृषक	02	0.0043

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति दस्तावेज सहित लिखित में कलेक्टर दुर्ग के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

(अभिजीत सिंह)
कलेक्टर जिला दुर्ग (छ0ग0)
एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जी- 262704772/2

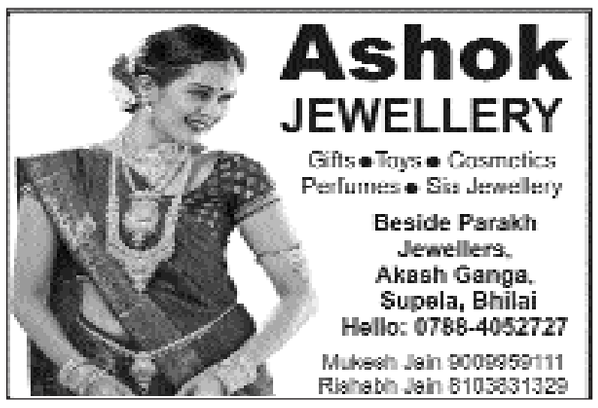





छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते

आर्थिक सुरक्षा
की दिशा में
सशक्त कदम



प्रधानमंत्री
जन-धन योजना

छत्तीसगढ़ में खुले
1.88+
करोड़
जन-धन खाते

Ro - 49814/8



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

/ChhattisgarhCMO
/DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950